छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

www.cgfrontline.com

RNI Reg No-CHHHIN/2020/87351

डाक पंजीयन क्र. 046/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 06 अंक - 62 बैकुंठपुर, मंगलवार 02 दिसंबर 2025 पृष्ठ -8 मूल्य -1

जिले के युवाओं को कौशल विकास के योजनाओं से करे लाभान्वित: कलेक्टर

जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव में खुलेगा शहीद वीर नारायण सिंह दाल भात केंद्र

- उद्यमिता विकास केंद्र के माध्यम से लोगों को बैंकिंग, जीएसटी एवं कर संबंधी मिलेगी जानकारी
- कलेक्टर ने बैठक में कार्ययोजना बनाने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वन, खनिज, उद्योग, श्रम, उद्योग व्यापार केंद्र, ग्रामोद्योग, अंत्यावसायी, कौशल विकास तथा आजीविका कॉलेज सहित संबंधित विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, मुख्यमंत्री घोषणाएँ, टीएल-जनदर्शन-पीजीएन, एसडीजी इंडिकेटर्स, पीएम सूर्यघर, ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएँ, विभागीय योजनाएँ, बजट उपयोगिता, ई-केवाईसी, स्थापना, कंडेम्ड वाहन, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस एजेंडा, निष्क्रिय बैंक खाते एवं अगले बजट हेतु प्रस्ताव जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विभागवार प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर श्री व्यास ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने दायित्वों का समयबद्ध निर्वहन करें और सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कौशल विकास विभाग को जिले के अधिक से अधिक युवाओं को इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मैकेनिक जैसे व्यवसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बैनर, पोस्टर एवं अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कर युवाओं को जागरूक करने कहा। इस दौरान सहायक कलेक्टर श्री अनिकेत अशोक सहित विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

कलेक्टर ने वन विभाग को टीएल में लंबित आवेदनों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। महाप्रबंधक उद्योग एवं व्यापार केंद्र को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्ष्यों की जानकारी लेकर अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने कहा। साथ ही जेम पोर्टल में उद्यमियों का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जशपुर नगर में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। यह केंद्र प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के माध्यम से बैंकिंग, जीएसटी, कर सहायता एवं उद्यमिता संबंधी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। लोगों को संबंधित जानकारी और उससे लाभ की प्रक्रिया एक ही जगह पर उपलब्ध हो पाएगी।

कलेक्टर श्री व्यास ने आबकारी विभाग को जिले में अवैध शराब की खरीदी, बिक्री एवं परिवहन पर सतत कार्रवाई करने निर्देशित किया। वहीं खनिज विभाग को अवैध खनन पर कड़ी निगरानी रखते हुए जेसीबी, चौन माउंटेन आदि उपकरणों से खनन की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल जप्ती की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने श्रम विभाग को महतारी जतन योजना सहित अन्य श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुँचाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जशपुर, कुनकुरी तथा पत्थलगांव में शहीद वीर नारायण सिंह दाल-भात केंद्र शीघ्र प्रारंभ करने कहा, जिससे आमजन को मात्र 5 रुपये में दाल-भात उपलब्ध हो सकेगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग आगामी बजट प्रस्तावों को नियमानुसार तैयार कर निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करें। उन्होंने विभागों से समन्वय बढ़ाते हुए जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देने को कहा।

अवैध धान खरीदी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 144 बोरी धान जब्त

चिरगुड़ा और टेलगा क्षेत्र में दो जगहों पर कार्रवाई, राइस मिल से जुड़े होने की आशंका

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। जिले में अवैध धान खरीदी पर निगरानी तेज करते हुए प्रशासन ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई कर कुल 144 बोरी धान जब्त किया है। दोनों मामलों में खरीदी बिना लाइसेंस के किए जाने की पुष्टि हुई है।

ग्राम चिरगुड़ा, पटना क्षेत्र में मीनाक्षी ट्रेडर्स द्वारा 38 बोरी धान अवैध रूप से खरीदा गया था। टीम ने मौके पर पहुंचकर धान को जब्त किया। अनुमानित वजन 19 क्विंटल, टेलगा पंचायत में किराना दुकान से 106 बोरी धान की जब्ती।उसी दिन ग्राम पंचायत टेलगा (बचरा-पोड़ी) के अंतर्गत एक किराना दुकान में बिना लाइसेंस के धान खरीदते 106 बोरी धान पकड़ा गया। दुकान के लड़के ने पूछताछ में बताया कि यह धान दीपक राइस मिल को भेजा जाना था। धान उपार्जन व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित रखने प्रशासन द्वारा सतत कार्रवाई की जा रही है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी आमजन की समस्याएं

छ.ग.फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज जिला कार्यालय में आयोजित जनदर्शन में आम नागरिकों से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याएँ एवं मांगों की जानकारी ली। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आवेदकों को उनके आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें अपनी समस्या के समाधान की स्थिति स्पष्ट रूप से ज्ञात हो सके। उन्होंने जनसुविधाओं से जुड़े प्रकरणों पर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज आयोजित जनदर्शन में कुल 27 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मुख्य रूप से राजस्व प्रकरण, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, अधोसंरचना निर्माण, आजीविका उन्नयन तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने संबंधित आवेदन शामिल थे।

महतारी वंदन योजना ने महिलाओं के जीवन में लाया साकारात्मक परिवर्तन

छ.ग.फ्रंटलाइन जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ग्राम पंचायत जोकारी की श्रीमती मंजू भगत भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। वे बताती हैं कि प्राप्त राशि से उनके परिवार के दैनिक खर्चों में उल्लेखनीय सहूलियत मिली है। यह सहायता वे किराना सामग्री खरीदने, बच्चों की शिक्षा में सहयोग, तथा स्वयं के छोटे-मोटे आवश्यक खर्चों पर उपयोग करती हैं। योजना से मिली आर्थिक सुरक्षा ने उनके परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे उनके जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा है।

एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों के पंजीयन की तिथि बढ़ी

जशपुरनगर। किसान हितों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत किसान पोर्टल पर कैरीफारवर्ड, डूबान तथा वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन हेतु निर्धारित समय सीमा बढ़ा दी गई है। विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अब यह प्रावधान 15 दिसम्बर 2025 तक सभी समितियों के समिति लॉगिन में उपलब्ध रहेगा। पूर्व में विभाग ने 30 नवम्बर 2025 तक इन प्रावधानों को समिति लॉगिन में उपलब्ध कराया था। किन्तु कैरीफारवर्ड, डूबान एवं वन पट्टाधारी कृषकों के पंजीयन की प्रक्रिया अभी जारी होने के कारण समय विस्तार आवश्यक पाया गया। इसलिए पंजीयन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2025 तक बढ़ाया गया है। पंजीयन तिथि बढ़ने से छुटे हुए किसानों को सहूलियत होगी।

शीतलहर के प्रभाव से बचने के लिए बरतें सावधानी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी

जशपुरनगर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जी. एस. जात्रा द्वारा आम नागरिकों से आग्रह किया गया है कि सर्दी को देखते हुए विशेष सावधानी बरते। गर्म कपड़े पहने, जैसे फ्लू, सर्दी, खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। सर्दी के मौसम में जब ठंडी हवाएं तेजी से चलने लगती है, तो तापमान में तेजी से गिरावट होने लगती है, तब इस स्थिति को शीत लहर कहते है। आसान शब्दों में कहा जा सकता है कि सर्दी के मौसम में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 04-05 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है, तो इसे शीत लहर कहा जाता है। स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के लिए रेडियो, टीवी. एवं समाचार पत्र जैसे सभी मीडिया द्वारा दी जा रही जानकारी का अनुसरण करें। पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े पहने। नियमित रूप से गर्म पेय पीते रहे।

जिला जलवायु परिवर्तन नोडल अधिकारी डॉ डी. के. अग्रवाल ने बताया है की शीत लहर के समय विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जैसे फ्लू, सर्दी, खांसी एवं जुकाम आदि के लक्षण हो जाने पर चिकित्सक से संपर्क करें। कम तापमान के लक्षण जैसे सामान्य से कम शरीर का तापमान, न रुकने वाली कंपकंपी, याददाश्त चले जाना, बेहोशी या मूर्छा की अवस्था का होना, जुबान का लड़खडाना आदि प्रकट होने पर चिकित्सक से संपर्क कर उपचार प्राप्त करें। शीत लहर के दौरान सॉवधानियां बरते पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े जैसे दस्ताने, टोपी, मफलर, एवं जूते आदि पहने, शीत लहर के समय चुस्त कपड़े ना पहने यह रक्त संचार को कम करते है, इसलिये हल्के ढीले-ढालें एवं सूती कपड़े बाहर की तरफ एवं ऊनी कपड़े अंदर की तरफ पहने, शीत लहर के समय जितना संभव हो सके घर के अंदर ही रहें और कोशिश करें कि अतिआवश्यक हो, तो ही बाहर यात्रा करें। जिला महामारी विशेषज्ञ सत्येन्द्र यादव द्वारा बताया गया की पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करें एवं शरीर की प्रतिरक्षा बनाए रखने के लिए विटामिन-सी से भरपूर फल और सब्जियां खाएं एवं नियमित रूप से गर्म तरह पदार्थ अवश्य पीयें, आवश्यकतानुसार रूम हीटर का उपयोग करें। रूम हीटर के प्रयोग के दौरान पर्याप्त हवा निकासी का प्रबंध आवश्य करें। शीत लहर में अधिक ठंड के लम्बे समय तक संपर्क में रहने से त्वचा कठोर एवं सुन्न हो सकती है।

जिले की सभी उपार्जन केन्द्र से 13900.40 क्विंटल हुई धान खरीदी

छ.ग.फ्रंटलाइन

एमसीबी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय ने किसानों को वह सम्मान मिला है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदी और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के अभूतपूर्व समर्थन मूल्य ने कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा, विश्वास और आर्थिक मजबूती का संचार किया है। इस खरीदी व्यवस्था से न सिर्फ किसानों को आर्थिक लाभ मिला है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यापारिक गतिविधियां तेज हुई हैं, कृषि उपकरणों की खरीद बढ़ी है, पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति सुलभ हुई है और किसान स्वावलंबन की दिशा में सशक्त कदम बढ़ा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में जाने से पारदर्शिता और त्वरित आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुआ है।

आज मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के सभी उपार्जन केंद्रों से प्राप्त विवरण के अनुसार धान खरीदी बेहद सफल और सुचारू रही। आज जिले में कुल 273 टोकन दर्ज किए गए जिनमें से समिति द्वारा 240 और टोकन एप्प के माध्यम से 33 टोकन जारी किए गए थे। समिति द्वारा कुल 11768.80 क्विंटल धान की खरीदी की गई तथा टोकन एप्प द्वारा 2131.60 क्विंटल धान खरीदी की गई, इस प्रकार आज कुल प्राप्त धान की मात्रा 13900.40 क्विंटल रही। उपार्जन केन्द्रवार खरीदी का पूरा विवरण इस प्रकार है - कछौड़ उपार्जन केन्द्र में 6 टोकन से 296.80 क्विंटल, कमर्जी उपार्जन केन्द्र में 8 टोकन से 383.40 क्विंटल, केल्हारी उपार्जन केन्द्र में 27 टोकन से 1066.80 क्विंटल, कोटाडोल उपार्जन केन्द्र में 9 टोकन से 404.00 क्विंटल, रापा उपार्जन केन्द्र में 6 टोकन से 220.40 क्विंटल, कटकोना उपार्जन केन्द्र में 12 टोकन से 618.00 क्विंटल, कोड़ा उपार्जन केन्द्र में 15 टोकन से 695.60 क्विंटल, कौड़ीमार उपार्जन केन्द्र में 19 टोकन से 758.80 क्विंटल, खड़गवां उपार्जन केन्द्र में 19 टोकन से 790.80 क्विंटल, बरदर उपार्जन केन्द्र में 11 टोकन से 600.00 क्विंटल, रतनपुर उपार्जन केन्द्र में 6 टोकन से 344.00 क्विंटल, सिंगहत उपार्जन केन्द्र में 4 टोकन से 230.40 क्विंटल, कंजिया उपार्जन केन्द्र में 7 टोकन से 466.40 क्विंटल, कुवांरपुर उपार्जन केन्द्र में 14 टोकन से 823.60 क्विंटल, घुटरा उपार्जन केन्द्र में 13 टोकन से 402.40 क्विंटल, कठौतिया उपार्जन केन्द्र में 11 टोकन से 437.20 क्विंटल, चैनपुर उपार्जन केन्द्र में 12 टोकन से 592.40 क्विंटल, बंजी उपार्जन केन्द्र में 9 टोकन से 518.40 क्विंटल, जनकपुर उपार्जन केन्द्र में 25 टोकन से 906.80 क्विंटल, बहरासी उपार्जन केन्द्र में 7 टोकन से 408.00 क्विंटल, डोड़की उपार्जन केन्द्र में 5 टोकन से 171.20 क्विंटल, नागपुर उपार्जन केन्द्र में 12 टोकन से 443.60 क्विंटल, बरबसपुर उपार्जन केन्द्र में 14 टोकन से 592.40 क्विंटल, माड़ीसरई उपार्जन केन्द्र में 17 टोकन से 920.00 क्विंटल और सिंगरौली उपार्जन केन्द्र में 17 टोकन से 809.00 क्विंटल की खरीदी दर्ज की गई। जिले के तीनों विकास खंडों के कुल 25 उपार्जन केन्द्रों से आज 13900.40 क्विंटल धान की खरीदी हुई है।

कृषि नीति ने बदला ग्रामीण अर्थव्यवस्था

जिले में किसानों की धान उपज का सुनियोजित और पारदर्शी तरीके से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार की कृषि नीतियां केवल कागज पर नहीं, बल्कि धरातल पर मजबूत परिणाम दे रही हैं। खरीदी व्यवस्था की दक्षता, भुगतान की पारदर्शिता, टोकन प्रणाली की विश्वसनीयता और प्रशासन की सक्रियता के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायी परिवर्तन आया है।

गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ द्वारा घर-घर सर्वे कार्य जारी एवं गणना पत्रक किए एकत्रित

छ.ग.फ्रंटलाइन

एमसीबी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और पूर्णतरू त्रुटि-रहित बनाने का कार्य तेजी के साथ जारी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार बूथ स्तर अधिकारियों को घर-घर जाकर मतदाताओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करना है और इसी क्रम में ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बीएलओ लगातार सक्रिय होकर क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। जनसंख्या एवं मतदान से जुड़ी सूचनाओं की सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर में जाकर गणना पत्रक एकत्रित किए जा रहे हैं। मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी तहसील के बीएलओ ने आज क्षेत्र का विस्तृत भ्रमण कर कृष्णा मुरारी तिवारी सहित कई नागरिकों से गणना पत्रक प्राप्त किए और संबंधित जानकारियों का मिलान भी किया। बीएलओ मतदाताओं को यह भी समझा रहे हैं कि सही जानकारी देना क्यों आवश्यक है और एक भी त्रुटि मतदाता सूची की विश्वसनीयता को कैसे प्रभावित कर सकती है। घर-घर सर्वे के दौरान मतदाताओं के नाम, पते, उम्र तथा अन्य आवश्यक तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है, साथ ही नए मतदाताओं के पंजीकरण, मृत व्यक्तियों के नाम हटाने, दोहराई गई प्रविष्टियों के सुधार तथा फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। बीएलओ ग्रामीणों को आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देकर उन्हें आवेदन भरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ताकि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके और कोई भी व्यक्ति मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। अभियान से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता बढ़ी है और नागरिक स्वयं भी अपने विवरण सही करने और नए नाम जोड़ने में रुचि दिखा रहे हैं। जिले में चल रहा यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि अद्यतन और त्रुटि-रहित मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। बूथ स्तर अधिकारियों की सक्रियता और नागरिकों के सहयोग से यह उम्मीद जताई जा रही है कि जिले की मतदाता सूची अधिक सटीक, सुव्यवस्थित और भरोसेमंद रूप में तैयार होगी जिससे चुनाव प्रक्रिया सुचारू तथा पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेगी।

756 केन्द्रों में लगभग 2 लाख 29 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

छ.ग.फ्रंटलाइन जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर को आयोजित की गई है जिसके लिए 756 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है। जहां प्रातः 12:00 बजे से 02:15 बजे तक परीक्षा आयोजित होगी। जिसमें लगभग 2 लाख 29 हजार 970 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 16 जिलों (अंबिकापुर, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव) में आयोजित की जा रही है। जिसमें राज्य के सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। जशपुर जिले के 12 निर्धारित परीक्षा केंद्रों में 4717 जिले के परीक्षार्थी शामिल होंगे। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व इन दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें और निर्धारित समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों व समुचित पहनावे के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। व्यापम द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के कम से कम 02 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए है। ताकि प्रवेश के पूर्व सभी अभ्यर्थियों का अनिवार्य रूप से फ्रिस्किंग समय पर किया जा सके। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखेंगे। परीक्षा में शामिल होने परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल हो (काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़ा पहनना वर्जित होगा)।

जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, डॉक्टर की गैरहाजरी से फंसा मामला

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। लटोरी चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत जगतपुर में रविवार को जमीन संबंधी पुरानी रंजिश अचानक हिंसा में तब्दील हो गई। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट से पूरे गांव में तनाव का माहौल हो गया। घटना के बाद घायल ग्रामीण जब उपचार और एमएलसी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लटोरी पहुंचे, तब वहां एक और चौंकाने वाला सच सामने आया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राजेश साव अस्पताल से गायब थे। सीएचसी लटोरी में पहुंचे पीड़ितों को बिना इलाज और बिना मेडिकल परीक्षण के बैरंग लौटना पड़ा। डॉक्टर की गैरहाजिरी से पूरी कानूनी प्रक्रिया अटक गई। गौरतलब है कि लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत जगतपुर में रविवार को जमीन संबंधी विवाद पर प्रार्थी प्रवेश कुशवाहा पिता रामप्रसाद कुशवाहा ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका भाई सुरेश कुशवाहा व नरेश कुशवाहा के अलावा भतीजा रूपेश कुशवाहा द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर दिया गया है और नरेश कुशवाहा द्वारा प्रार्थी को दांत से भी काट लिया गया

है। वहीं दूसरी ओर प्रार्थी नरेश कुशवाहा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि भाई प्रवेश कुशवाहा के अलावा प्रमोद, विनोद, उत्तम देवी द्वारा जान से मारने की धमकी देकर मारपीट किया गया है। दोनों पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने जब लटोरी सीएचसी में एमएलसी हेतु भेजा तो वहां पर ड्यूटीरत चिकित्सक राजेश साव कार्यस्थल से नदारत थे, जिससे पीड़ित पक्षों का मुलायजा नहीं हो सका। सोमवार को जब पुन: पीड़ित पक्षों को लेकर लटोरी पुलिस सीएचसी पहुंची, तब दूसरे चिकित्सकों ने एमएलसी करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि जो चिकित्सक ड्यूटी पर थे वही एमएलसी करेंगे। पीड़ितों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही की शिकायत सीधे अधिकारियों तक पहुंचाई। सोमवार सुबह होते-होते पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद सीएमएचओ डॉ. कपिलदेव पैकरा, एसडीएम शिवानी जायसवाल, बीएमओ डॉ. अमित भगत ने तत्काल हस्तक्षेप किया। अधिकारियों के निर्देश मिलते ही अस्पताल स्टाफ हरकत में आया, और अंतत: दोनों पक्षों का एमएलसी कराया गया। इसके बाद लटोरी पुलिस ने दोनों ओर से दर्ज शिकायतों के आधार पर काउंटर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। इस पूरे प्रकरण ने सुरजपुर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टरों का ड्यूटी से नदारत रहना आम बात हो चुकी है।स्थानीय लोगों का आरोप है कि रविवार को अधिकांश डॉक्टर नदारत रहते हैं। दवा, डॉक्टर, परीक्षण कुछ भी समय पर नहीं मिल पाता है। स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चल रहा है। क्षेत्रवासियों ने डॉ. राजेश साव की ड्यूटी में अनुपस्थिति को गंभीर लापरवाही बताते हुए विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। घटना सिर्फ एक मारपीट का नहीं, बल्कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को दिखाती है।

चिकित्सक को नोटिस हुआ जारी

ड्यूटी से नदारत रहने वाले चिकित्सक राजेश साव को बीएमओ डॉ. अमित भगत द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर नोटिस जारी करके दो दिन जवाब मांगा गया है। नोटिस के जवाब मिलने उपरांत अग्रिम कार्यवाही की बात विभागीय अधिकारियों द्वारा कही जा रही है।

कुमदा सब एरिया मैनेजर पर जानलेवा हमला का प्रयास

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। एसईसीएल बिश्रामपुर के कुमदा सब एरिया मैनेजर पर सोमवार दोपहर जानलेवा हमला का प्रयास किया गया, जिसमें वे बाल बाल बच गए हैं। घटना में उनकी सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचा है।

बताया जा रहा है कि कुमदा सहक्षेत्र प्रबंधक अश्विनी चंद्रा सोमवार को सरकारी वाहन सीजी 29 एएच 8369 से खदान से कॉलोनी लौट रहे थे। तभी दोपहर करीब सवा दो बजे कुमदा साइडिंग के पास तीन अज्ञात स्कूटी सवारों ने उनके वाहन को रुकवा लिया, जिसमें एक व्यक्ति ने स्कूटी को उनके वाहन के सामने लगा दिया जबकि दो अन्य बदमाशों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला का प्रयास किया, जिसमें वे बाल बाल बच गए। घटना में उनके वाहन का शीशा टूट गया। हो हल्ला के बाद तीनों बदमाश स्कूटी के साथ मौके से भाग निकले। घटना के बाद सहक्षेत्र प्रबंधक ने उच्चाधिकारियों को मामले की सूचना देकर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कराने थाने पहुंचे हैं।

ज्ञात हो कि एक दिन पूर्व आरजीके के कार्मिक प्रबंधक रेशम लाल के कार पर भी स्कूटी सवार युवकों ने मानी गांव के समीप पथराव की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उनके निजी कार के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आज उन्होंने घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस को लिखित में दी है। खदान के अधिकारियों को अपराधियों द्वारा निशाना बनाए जाने की घटना के बाद अधिकारी कर्मचारी सकते में आ गए हैं। पथराव करने वाले कौन हैं, उनकी मंशा क्या है यह स्पष्ट नहीं हो सका है लेकिन दोनों मामलों में स्कूटी सवारों द्वारा घटना को अंजाम देने और दोनों ही मामलों में तीन तीन युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। बिश्रामपुर टीआई प्रकाश राठौर ने बताया कि घटना के संबंध में शिकायतकर्ता से आवश्यक पूछताछ के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक 02 दिसम्बर 2025 को समय-सीमा की बैठक पश्चात संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत अद्यतन प्रगति की समीक्षा एवं विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।

लटोरी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रम की हुई शुरुआत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन संत हरिश्याम संस्कृत विद्यापीठ लटोरी में 1 से 7 दिसंबर के बीच किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ मां काली सेवा आश्रम लटोरी के सुखदेव मुनि के मुख्य आतिथ्य में किया गया। अन्य अतिथियों में डॉ. एसके श्रीवास्तव प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर, दिवाकर वैष्णव उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने गीता के महत्व के बारे में बताते हुए कहा की गीता हमारे समाज का सबसे पवित्र ग्रंथ है, इसका हर श्लोक महामंत्र है। यह हमारे जीवन जीने की शैली को

सिखाता है। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ. एसके श्रीवास्तव ने कहा कि गीता हमें कर्मयोगी बनाने के साथ ही हमें हर समय अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। विपरीत समय में जीवन जीने की कला को सिखाता है। दिवाकर वैष्णव अध्यक्ष संत समाज सूरजपुर ने कहा कि हर छात्र को गीता पर प्रतिदिन तुलसी के पत्ती से पूजा करना चाहिए, इससे स्मरण शक्ति में वृद्धि होता है। कार्यक्रम में प्रत्येक छात्र को गीता की पुस्तक भेंट किया गया। विद्यालय के रहमदिल अंसारी ने कहा कि गीता सभी धर्मों का सर्व मान्य ग्रन्थ है, इसका पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। यूवी संस्कार स्कूल लटोरी के प्राचार्य उमाशंकर यादव ने कहा कि इस भाग दौड़ की दुनिया में गीता हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान यूवी संस्कार महाविद्यालय लटोरी की प्राचार्य शिल्पी श्रीवास्तव, शिक्षिका तुलसी, सीमा राजवाड़े, तारामानी राजवाड़े, अल्फा मरावी के अलावा संत हरिश्याम संस्कृत विद्यापीठ लटोरी के सभी छात्रों ने हिस्सा लिया। महोत्सव के दौरान प्रति दिन सप्ताह भर गीता का पाठ का वाचन एवं गीता का व्याख्या विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा।

धंधापुर में ग्रामीणों की सहमति एवं अधिकारियों के देख-रेख में किया जा रहा पुलिया निर्माण

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री जे.आर. सोनवानी ने जानकारी दी है कि जिले के राजपुर जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धंधापुर में चल रहे पुलिया निर्माण के संबंध में कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित मानकों को दरकिनार कर किया जा रहा पुलिया का निर्माण के संबंध में स्वयं उपस्थित होकर निर्माण कार्य का जांच किया गया। उन्होंने बताया है कि निर्माण कार्य की लागत राशि 20 लाख रुपये की है। इसकी गहराई 1.70 मीटर किया गया है तथा अबाटमेंट की ऊंचाई 2.10 मीटर है। प्राक्कलन में सिर्फ स्लैब में छड़ का प्रावधान किया गया है। जांच में छड़ लगा पाया गया। अबाटमेंट एवं विंगवॉल में छड़ का प्रावधान प्राक्कलन में नहीं किया गया है। इसलिए इसमें छड़ का उपयोग नहीं किया गया है। पुलिया के स्लैब में 880 किलोग्राम छड़ का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है, जो उपयोग में किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी श्री सोनवानी ने बताया कि पूर्व में निर्माणाधीन पुलिया सिंचाई विभाग से बन रहा था, चूंकि वह रास्ता परिवर्तन कर ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जा रहा था। ग्रामीणों के मांग एवं पंचायत प्रस्ताव के आधार पर ही यह पुलिया स्वीकृत है। ग्रामीणों की सहमति एवं तकनीकी अधिकारियों के देखरेख में पुलिया निर्माण कार्य की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री जे.आर. सोनवानी ने बताया कि पुलिया प्राक्कलन अनुसार निर्धारित मापदंड में बनाया जा रहा है।

195 बोरी अवैध धान जब्त, राजस्व विभाग की टीम ने की कार्यवाही

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 15 नवम्बर 2025 से धान खरीदी शुरू हो चुकी है और

धान के अवैध परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर श्री अभिषेक गुप्ता के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग की टीम के द्वारा बलरामपुर से चांदो 02 ऑटो में परिवहन किया जा रहे धान को जब्त किया है। तहसीलदार श्री रवि भोजवानी ने बताया कि 02 ऑटो में 35 बोरी धान रखकर अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसे राजस्व विभाग की टीम के द्वारा जांच की गई तथा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही करने पर जब्त कर चौकी गणेशमोड को सुपुर्द किया गया है। इसी प्रकार ग्राम राधाकृष्णनगर निवासी श्री हेमंत सरकार के घर में राजस्व विभाग की टीम ने 160 बोरी अवैध रूप से भण्डारित धान जब्त किया है।

अब तक 46 प्रकरणों 4430 क्विंटल धान और 21 वाहन जब्त

कलेक्टर राजेंद्र कटारा के निर्देशन में जिले में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने सभी अंतरराज्यीय सीमाओं एवं चेक पोस्टों पर चौकसी को और मजबूत करते हुए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके तहत संदिग्ध वाहनों, परिवहन गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पारदर्शी एवं निष्पक्ष धान खरीदी नीति के तहत अब तक जिले में कुल 46 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4430 क्विंटल अवैध धान एवं 21 वाहनों को जब्त किया गया है, जो कि प्रशासन की सतत निगरानी तथा संयुक्त दलों की सक्रियता का परिणाम है।

कलेक्टर श्री कटारा के मार्गदर्शन में सभी अंतरराज्यीय एवं आंतरिक चेक पोस्टों पर भी टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रत्येक अनुविभाग में गठित निगरानी दल रात्रि कालीन गश्त के साथ ही आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच कर रहे हैं और मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई कर रही हैं। कलेक्टर श्री कटारा ने आम नागरिकों एवं किसानों से अपील की है कि यदि अवैध धान परिवहन या भंडारण से संबंधित कोई भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना मिले तो तुरंत सूचित करें। जिसमें सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

गलत तरीके से नौकरी की पीएमओ कार्यालय में हुई शिकायत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। रेहर भूमिगत खदान में कर्मचारियों के खिलाफ प्रधानमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत ने अब बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट रूप ले लिया है। जहां अधिकांश मजदूरों को यूनियन के हस्तक्षेप के बाद काम पर वापस लौटा दिया गया है, वहीं अब कर्मचारियों के समक्ष भूखों मरने की नौबत आ गई है।आरोपों की गंभीरता, कर्मचारियों की बेबसी और प्रबंधन के रवैये ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। प्रधानमंत्री के पोर्टल में शिकायत उपरांत एसईसीएल प्रबंधन द्वारा रेहर खदान में कार्यरत सूरजन पिता मोहर साय, भग्गू पिता गेदला, लालदेव पिता वासुदेव, विजय पिता घासी, हसतम पिता राजूराम, रतीराम पिता जगमोहन, वंशू पिता बाबूलाल, भुकनाथ पिता वालम, कृपाल सिंह पिता अर्जुन, हीरालाल पिता जुलुग, शिवबालक पिता रामदेव, बीरबल पिता मोहरलाल, प्रेमसाय पिता दलसाय, माझी सहित कई कर्मचारियों को कार्य से बैठा दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चमरू राम पिता प्राणसाय और रामचंद्र पिता देवसाय जैसे अब दिवंगत

कर्मचारियों के नाम भी शिकायत में दर्ज किए गए हैं। प्रधानमंत्री पोर्टल में दर्ज कराए गए शिकायत में शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि कई कर्मचारी स्वयं कार्य करने में असमर्थ हैं और अपनी असली ड्यूटी की जगह अपने पुत्रों या रिश्तेदारों को खदान में भेजते हैं और इस पूरे मामले में प्रबंधन भी मौन सहमति देता है। जबकि बताया जा रहा है अधिकांश मजदूर दुर्घटनाओं में घायल होने के कारण खदान के भीतर कार्य करने योग्य नहीं हैं।शिकायत की सूचना पर शुरू हुए जांच के बाद रेहर खदान प्रबंधन ने सभी शिकायत के शिकार हुए कर्मचारियों को काम से बैठा दिया है। जिससे मजदूर परिवारों पर संकट गहरा गया है। स्थानीय कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों और प्रबंधन के बीच साठगांठ कर बेबुनियाद शिकायत को आधार बनाकर मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। कुछ लोगों के निजी हितों और आपसी रंजिश के चलते मजदूरों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा सरफेस में कार्यरत सभी कर्मचारियों को चिन्हांकित कर कर्मचारियों को दिए गए भूमिगत भत्ता की कटौती की जा रही है एवं ऐसे कामगार जो अस्वस्थ लग रहे हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण केंद्रीय चिकित्सालय बिश्रामपुर में करवाया जा रहा है। साथ ही भूमिगत रोल के कर्मचारी जो काम करने में असक्षम हैं, उन्हें बिलासपुर स्पेशल मेडिकल बोर्ड में भेज कर स्वास्थ्य परीक्षण करवाने की बात कही जा रही है।

प्रबंधन ने अब उठाया कदम

एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के कई सहक्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रबंधन भी श्रमिक नेताओं के दबाव में ऐसे अवैध कार्य को अंजाम दिए जाने मजबूर दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व में भी शिकायतें कई बार की गई लेकिन प्रबंधन ने इस ओर ध्यान देना उचित नहीं समझा था। अब पीएमओ कार्यालय में शिकायत के बाद प्रबंधन हरकत में आकर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिससे प्रबंधन व श्रमिक नेताओं के बीच तनातनी की स्थिति निर्मित हो रही है।

निधन देवंती देवी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगर सेना सुरजपुर में मेजर व ग्राम पंचायत कुंजनगर निवासी विनय कश्यप की मां देवंती देवी पति सेवानिवृत्त कोलकर्मी स्व. बनारसी राम का गत दिनों हृदयागति रुकने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष की थीं। उनका अंतिम संस्कार बनारस में हरिश्चंद घाट पर किया गया, जिन्हें मुखाग्नि पुत्र विनय कश्यप ने दी।

वे अपने पीछे दो पुत्र व दो पुत्री समेत भरापुरा परिवार शोकाकुल छोड़ गई हैं।

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत परीक्षा 07 को

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के असाक्षरों को सत्र 2030 तक साक्षर कर पूरे देश को पूर्ण साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2022 से 2027 तक उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका संक्षिप्त नाम उल्लास प्रौढ़ शिक्षा को अब सबके लिए शिक्षा का नाम दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेन्द्र कटारा ने उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत जिले वासियों से अपील किया है कि राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान में 07 दिसम्बर 2025 को बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के 15 वर्ष से

अधिक आयु के ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने उल्लास साक्षरता केन्द्र में 200 घण्टे में 7 अध्याय पूर्ण किये हों अवश्य भाग लें और सफल होकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एनआईएलपी का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। उन्होंने कहा है कि बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ हमें उन व्यक्तियों की ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जो पहले किन्ही कारणों से पढ़-लिख नहीं पाये हैं। उल्लास कार्यक्रम इसी दिशा में राष्ट्रव्यापी पहल है।

जिला परियोजना अधिकारी साक्षरता मिशन श्री हीरालाल पटवा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रव्यापी महापरीक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए जिले में 573 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिसमें 27603 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

अवैध रेत उत्खनन व परिवहन करते पाये जाने पर 05 ट्रैक्टर जब्त

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने जिले में खनिज के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। जिसके तहत् राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम द्वारा अवैध उत्खनन व परिवहन करने वालों कार्यवाही की गई है।

प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम बसंतपुर के अंतर्गत लेदो नदी में 03 ट्रैक्टर एवं कैलाशपुर 02 ट्रैक्टर में अवैध रूप से रेत का उत्खनन व परिवहन किया जा रहा था, जिसे तहसीलदार एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जांच किया गया। जांच में सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर तीन ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस थाना बसंतपुर तथा 02 ट्रैक्टर को वाड्रफनगर चौकी को सुपुर्द किया गया है।

कृष राजवाड़े राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर - हायर सेकेंडरी स्कूल कृष्णपुर विकासखंड - रामानुजनगर के कक्षा 9वीं के प्रतिभावान छात्र कृष राजवाड़े ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। हाल ही में आयोजित बालक तीसरा छत्तीसगढ़ क्वान किडो चैम्पियनशिप 2025 में कृष राजवाड़े ने दमदार प्रदर्शन किया और स्वर्ण पदक हासिल कर सबका ध्यान आकर्षित किया। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कृष का राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। अब कृष राजवाड़े जनवरी 2026 में जम्मूझ्रकश्मीर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय क्वानझ्रकिडो चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। कृष की इस उपलब्धि से प्राचार्य श्रवण कुमार वरकड़े, पीटीआई सुनीता राजवाड़े, व्याख्याता चंद्रकेश शर्मा सहित विद्यालय परिवार, शिक्षकगण और सहपाठियों में अपार हर्ष और गर्व का वातावरण है। विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि कृष की यह सफलता मेहनत, लगन और अनुशासन का परिणाम है, जो अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। विद्यालय परिवार ने कृष राजवाड़े को उनकी इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन की शुभकामनाएँ प्रदान की हैं।

बी. आर. हितकर ने मूल प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण किया

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर।स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय भुवनेश्वरपुर में आज एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन के तहत बी. आर. हितकर ने मूल प्राचार्य पद का कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण समारोह जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यग्रहण के पश्चात नवपदस्थ प्राचार्य बी. आर. हितकर ने विद्यालय के समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ से परिचय प्राप्त किया तथा उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण एवं मानक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में अनुशासन, शिक्षकीय सामंजस्य, छात्रहित एवं नवाचार आधारित गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में संकल्पित होकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए टीमवर्क, सृजनात्मक वातावरण और पारदर्शी कार्यप्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा।

अचल संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के गाइडलाइन पर पूर्व विधायक ने दी तीखी प्रतिक्रिया

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भैयाथान। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अचल संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए निर्धारित गाइडलाइन दरों में 20 प्रतिशत से लेकर 10 गुना तक की अभूतपूर्व बढ़ोतरी ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। मध्यवर्गीय परिवारों के सिर पर जमीन और मकान खरीदने का बोझ अचानक कई गुना बढ़ जाने से आम जनता में गहरा रोष दिखाई दे रहा है। सरकार के फैसले पर भटगांव के पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस निर्णय को तुगलकी फरमानह्व बताते हुए आशंका जताई कि इसकी परिणति भी जीएसटी और नोटबंदी जैसी अव्यवस्था में हो सकती है। राजवाड़े ने कहा कि गाइडलाइन दरों की यह उछाल सीधे-सीधे जनता की पहुँच को खत्म कर देगी। भाजपा अब लोगों को मालिक नहीं, किराएदार बनाकर रखना चाहती है,ह्व उन्होंने आरोप लगाया। उनके अनुसार अब गाइडलाइन दरें स्थानीय बाजार मूल्य से भी ऊपर पहुँच गई हैं, जिसके कारण रजिस्ट्री शुल्क पहले से कई गुना अधिक चुकाना पड़ेगा। प्रदेशभर में लोग भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और मंत्रियों से इस निर्णय को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कई स्थानों पर नागरिकों ने प्रतिनिधियों को घेरकर अपना विरोध भी दर्ज कराया है। राजवाड़े ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में तथाकथित मोदी गारंटीह्व अब छत्तीसगढ़ लूट की पक्की गारंटीह्व बनती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगलों को उजाड़कर उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारियाँ जारी हैं, जिससे रामगढ़ पर्वत जैसी ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहरें संकट में हैं। उनका दावा है कि अब बस्तर की प्राकृतिक संपदाओं पर भी निगाहें टिकाई जा चुकी हैं और सरकार के संरक्षण में पूरी योजना बनाई जा रही है।

किसान तुंहर टोकन ऐप से देव प्रकाश साहू बने डिजिटल व्यवस्था के लाभार्थी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। जिले में धान खरीदी व्यवस्था में तकनीक के बढ़ते उपयोग से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। अब किसान तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे धान विक्रय के लिए टोकन काट रहे हैं। जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है। ग्राम पंचायत गुगराखुर्द के किसान देव प्रकाश साहू इसका एक सशक्त उदाहरण हैं, जिन्होंने बताया कि किसान तुंहर टोकन ऐप से टोकन कटाना अब बेहद आसान हो गया है। वे अपनी 4.5 एकड़ जमीन के रकबा में 94 क्विंटल धान का टोकन घर बैठे ही प्राप्त किया है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत हुई। किसान देव प्रकाश साहू निमहा धान उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां डिजिटल प्रक्रिया और सुचारू व्यवस्था ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्र पहुंचे, बारदाना तुरंत उपलब्ध कराया गया और इलेक्ट्रॉनिक कांटा से धान की तुलाई बिना किसी देरी के की गई। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता साफ दिखाई दी।

किसान देव प्रकाश ने खरीदी व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस बार धान खरीदी में तकनीक का उपयोग बढ़ा है। ऐप से लेकर तुलाई तक, सबकुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार में 3100 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिलने से न सिर्फ किसानों को आर्थिक मजबूती मिली है, बल्कि खेती को लेकर उनके उत्साह में भी बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना है कि सरकार की डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से हम किसानों का भरोसा और बढ़ा है। अब खरीदी के दौरान समय की बचत होती है और पूरा काम बिना विवाद पूरा हो जाता है। इस वर्ष धान खरीदी में डिजिटल तकनीक ने किसानों को बड़ी राहत दी है, जिससे देव प्रकाश साहू जैसे किसान कृषि व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल कर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन ला रहा है।

राष्ट्रीय डायलिसिस टेक्नीशियन कॉन्फ्रेंस का अंबिकापुर में प्रथम आयोजन

संयुक्त आयोजन: लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, अंबिकापुर एवं होलीक्रॉस हॉस्पिटल, अंबिकापुर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सरगुजा किडनी केयर एसोसिएशन अंबिकापुर ने शहर में चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल और होलीक्रॉस हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में प्रथम राष्ट्रीय डायलिसिस टेक्नीशियन कॉन्फ्रेंसह्व का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर डायलिसिस टेक्नीशियनों को राष्ट्रीय मानक की तकनीकी दक्षता, उन्नत ज्ञान एवं आपातकालीन प्रबंधन क्षमता प्रदान करना था।

वैज्ञानिक सत्र एवं विशेषज्ञ व्याख्यान

सम्मेलन में उन्नत डायलिसिस प्रोटोकॉल्स, सीआरआरटी तकनीक, एकेआई प्रबंधन, व्यस्कुलर एक्सेस केयर, फ्लूइड डायनामिक, एंटिकोगुलेशन एवं कोम्प्लिकेसन हैंडलिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत वैज्ञानिक चचाएँ की गईं। मुख्य वक्ता के रूप मे डॉ. सुनील धमार्नी, डीएम नेफ्रोलॉजी, डॉ. प्रतीक खरे, एमडी.मेडिसिन, डॉ. अविना, डीएम एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, डॉ. संदीप सिंगल डी.एम. नेफ्रोलॉजी, डॉ. उत्तम सिंह, डीएम नेफ्रोलॉजी। इन सभी विशेषज्ञों ने एविडेंस बेस्ड पार्टिकल और इमरजेंसी ओरिएंटेड क्लिनिकल इनसाइट प्रदान किए, जो उपस्थित टेक्नीशियनों के लिए अत्यंत मूल्यवान सिद्ध हुए। सम्मेलन की सफलता में सीनियर सिस्टर ममता, एडमिनिस्ट्रेटर, होलीक्रॉस हॉस्पिटल , प्रयंक खरे, डायरेक्टर, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल , डॉ. दीक्षा खरे, मैनेजिंग डायरेक्टर, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, टंकाधर बारिक, चेयरपर्सन, सरगुजा किडनी केयर एसोसिएशन एवं सीनियर डायलिसिस तकनीकी सहायक, होलीक्रॉस हॉस्पिटल अंबिकापुर , प्रिंस कुमार, चेयरपर्सन, साइंटिफिक कमेटी एवं सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन, लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल अंबिकापुर तथा होलीक्रॉस हॉस्पिटल की संपूर्ण वरिष्ठ नर्सिंग एवं तकनीकी टीम का उल्लेखनीय योगदान रहा।

सम्मेलन का उद्देश्य

डायलिसिस टेक्नीशियनों को राष्ट्रीय-मानक क्लिनिकल और तकनीकी कौशल प्रदान करना , जटिल एवं आपातकालीन डायलिसिस स्थितियों में सुरक्षित, त्वरित एवं सबूत के आधार पर निर्णय को सशक्त करना , सरगुजा क्षेत्र में किडनी की देखभाल उत्कृष्टता को राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचाना , सीआरआरटी एवं उन्नत गुर्दा प्रतिस्थापन चिकित्साका क्षेत्रीय विस्तार करना है। अंबिकापुर अब नेफ्रोलॉजी, डायलिसिस एवं क्रिटिकल केयर सेवाओं में राष्ट्रीय उत्कृष्टता का केंद्र बन रहा है। यह सम्मेलन उसी दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरगामी कदम है।

किसानों को निःशुल्क सरसों बीज वितरण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के विकासखंड सोनसत कृषि विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर गत दिवस को निःशुल्क सरसों बीज का वितरण किया गया। उक्त आयोजन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सोनहत द्वारा किया गया। जिसमे कृषि विभाग के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (धान -चना) योजना अंतर्गत सरसों बीज का वितरण किया गया। जनपद पंचायत सोनहत क्षेत्र के ग्राम पंचायत मधौरा सरपंच अमर साय के उपस्थिति में वितरण किया।उल्लेखनीय है कि कोरिया कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर खाद एवं पोषण सुरक्षा योजना के तहत वितरण क्षेत्र मधौरा के कई क्षेत्रों से आए किसानों को सरसों बीज का वितरण किया गया। वहीं कृषि अधिकारियों ने किसानों को सरसों की उन्नत किस्म के गुणो को रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा कम लागत में अधिक उत्पादन के उपाय बताएं। इस दौरान उप संचालक कृषि राजेश कुमार भारती,एसडीओ लाल सिंह आरमो, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मान सिह मरावी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दिनेश पटेल ,हीरा केवट उपस्थित रहे।

निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

युवा स्वास्थ्य टीम के द्वारा नगर पंचायत पटना के अंतर्गत ग्राम पंचायत जमड़ी मेंदिनांक 07. 12.2025 को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जायेगा, जिसमें डॉ रितेश कुशवाहा, डॉ शास्वती संतरा,डॉ शिवानी अग्रवाल,एवं डॉ निष्ठा अग्रवाल व उनकी टीम अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में ,1.सामान्य एवं मौसमी बीमारियों का उपचार 2 गंभीर बीमारियों के लिए उचित सलाह 3. महिलाओं से संबंधित रोगों का उपचार एवं सलाह4. मुख एवं दांत संबंधी रोगों का उपचार एवं सलाह5. शुगर, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स वजन, आदि की जांच।

चॉकलेट का लालच देकर 4 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले से बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक चार वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है। इस दरिंदगी को अंजाम एक 16 साल के नाबालिग लड़के ने दिया। 16 साल के नाबालिग आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने बच्ची के साथ बलात्कार किया।

16 साल के लड़के ने 4 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म

मामला बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है. आरोपी 16 वर्षीय नाबालिग लड़का है। लड़के ने 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर बच्ची को अपने पास बुलाया और फिर उसके साथ दरिंदगी की। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया।

बच्ची की तबियत बिगड़ने पर हुआ खुलासा

इस मामले के खुलासा तब हुआ जब बच्ची की तबियत बिगड़ी। बच्ची की तबियत बिगड़ने पर परिजनों को शक हुआ। उन्होंने बच्ची से पूछा तो अपने साथ हुई आपबीती के बारे में मासूम ने बताया। जिसके बाद परिजन ने तत्काल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। उन्होंने बच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा. साथ ही पुलिस की टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा. वहीँ, इस मामले में परिजन और स्थानीय लोग ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है।

खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा को नायक बनाने की कोशिश!

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

खूंखार नक्सल कमांडर माडवी हिडमा को सुरक्षाबलों द्वारा ढेर कर दिया गया। पैंतालिस वर्षीय हिडमा पर छः राज्यों ने इनाम घोषित किया था,जिसकी कुल राशि एक करोड़ अस्सी लाख रूपए थी। हिडमा की मौत आतंक के एक युग का अंत है। लेकिन जिस तरह से उसकी शव यात्रा में ग्रामीणों का सैलाब देख कुछ स्वंयभू बुद्धिजीवी हिडमा को जननायक के रूप परोसने का बौद्धिक विज्ञापन कर रहे है। लेकिन अचरज की बात नहीं ये वही विचारधारा है, जो संसद में हमले के योजनाकार अफजल गुरू की फांसी का विरोध करती है। 26/11 के आतंकवादी अबु अजमल कसाब को बिरयानी खिलाती है। कसाब के लिए रात मे 12 बजे पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा देती है। ऐसे वकील भी है जो कानून का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा से घात कर आतंकियों का पक्ष लेते है। ये वही लोग है जो मुंबई ब्लास्ट के आरोपी याकूब मेनन, तो कभी आतंकी बुरहान बानी के जनाजे शामिल भारी भीड़ के द्वारा उन्हें भी हीरो बनाने की कोशिश करती है। इसी तर्ज पर वे हिडमा को जननायक बता रहे है। जनसंहारक को जनननायक बनाने की सोच असुर दशानन से महिर्षि रावण बनाने वाली कुत्तिस सोच है। यह मृगतृष्णा और मूर्खता की अंतहीन यात्रा है। लेकिन हिडमा की शव यात्रा मे हजारों की संख्या को असमान्य रूप से भी देखा जाना चाहिए। 25 मई 1967 को भूमि अधिकार को लेकर चारू मजूमदार, कान्हू सन्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व मे दार्जलिंग जिले के नक्सलवाडा से जन्मा आंदोलन जो कभी पेरियार घाटी तक विस्तृत था। जिसका सर्वाधिक दंश यदि किसी ने झेला है तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, आध्रप्रदेश व झारखंड है।

माडवी हिडमा की मौत उस आतंक के ताबूत ने अंतिम कील है। लेकिन इस कील को अपनी मजबूती सिद्धं करना अभी शेष है?

अभी वामपंथ जेएनयू के छात्रों नें दिल्ली मे शुद्ध हवा के लिए आंदोलन की आड़ में हिडमा को नायक बताने एक छद्मवेषी आंदोलन किया। जेएनयू जहां भारत तेरे टुकड़े होगे इंशालाहा, हर घर से अफजल और हिडमा निकलेगा जैसे देशद्रोही नारे लगते है। ऐसी मानसिकताता का आधार, जेएनयू और एएमयू की संयुक्त विचारधारा है और बीबीस समाचार इनका सबसे बड़ा प्रचारतंत्र है। हिडमा को नायक कहने वाले यही लोग हिडमा द्वारा कारित जघन्यतम झीरम घाटी हमला और इस घटना मे शामिल हिडमा सहित सभी नक्सलियों पर सख्त कार्यवाही करने का दबाव डालते है और अब हिडमा मौत पर उसे नायक कहते है। गजब की धूर्तत्ता है?

ऐसे लोग जो नक्सलवाद को अपने ही अवशेषों से पुनर्जीवित हो उठने वाले यूनानी दंतकथा के पक्षी फिनिक्स की तरह अमर मानते है। ऐसे ही हिडमा को जननायक मान, नक्सलवाद के पुनर्जीवन की कुत्तिस कल्पना भी कर है। ऐसे लोगो से पूछा जाना चाहिए कि मार्च 2007 उरपल मेट्टा मे 24 सीआरपीएफ जवानो, अप्रैल 2010 मे ताडमेटला में 76 और ऐराबोर की घटना मे सैकड़ो आम नागरिको सहित सुरक्षाबलो का हत्यारा। झीरम घाटी जिसमे छग कांग्रेस का कुनबा खत्म हो गया। झीरम घाटी जो विश्व की सबसे बडी राजनैतिक नरसंहार था और ऐसे कई नरसंहारो का खलनायक है,जननायक कैसे हो सकता है?

जहां तक उसके अंतिमयात्रा में शामिल भीड़ की है इसमे कुछ हिडमा के परिवार और रिश्तेदारों का, तो भीड़ का एक बड़ा हिस्सा हिडमा के सुर्खियों के कारण उसकी शवयात्रा में सम्मिलित हुआ क्योंकि पूरे विश्व में भीड़ का समाज शास्त्र और मनोविज्ञान एक सा होता है। हिडमा की मौत पर जो उसे जननायक बताने वाली वैचारिक जद्दोजहद चाय की केतली में तूफान से अधिक कुछ नही। सांप के दांत मे, मक्खी के सिर मे ,बिच्छु के पूंछ में विष होता है, लेकिन नक्सलवाद का पूरा शरीर ही विषाक्त है। छत्तीसगढ़ मे नक्सलवाद और हिडमा को निर्मूल करने के लिए डीजीपी सहित पूरी पुलिस टीम प्रशंसा की पात्र है। हाल में ही रायपुर मे संपन्न डीजी कांफ्रेस मे देश आंतरिक सुरक्षा के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी।

मनोज कुमार सिंह

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर घर में घुसी, गाड़ी को काटकर निकाला गया चालक का शव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कच्चे घर में जा घुसी। इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार को काटकर उसके अंदर से चालक के शव को बाहर निकाला गया।

कच्चे मकान में घुसी कार

यह घटना करंजी चौकी क्षेत्र में हुई है। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कच्चे मकान में जा घुसी। घटना के बाद कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। टक्कर कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इस घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कार को काटकर निकाला गया शव

जानकारी के मुताबिक, कार 30 नवंबर की रात धरतीपारा से खोपा की ओर जा रहा था। तभी वह अनियंत्रित होकर घर की दीवार तोड़कर अंदर जा घुसी। टक्कर के बाद कार बुरी तरसे चकनाचुर हो गया। इधर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार को काटकर उसके अंदर से चालक के शव को निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस

शुरूआती जांच में पता चला कि मृतक धरतीपारा का रहने वाला था और 30 नवंबर की रात खोपा की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार करंजी चौकी क्षेत्र में अनियंत्रित होकर एक घर की दीवार को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। इस घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

सम्पादकीय

सत्र के आर, सत्र के पार

तपोवन में क्या आगामी विधानसभा चुनाव की रंगभूमि रची जा रही है। सोशल मीडिया सदन के बाहर जिस सत्र की ताजपोशी करता रहा वहां क्या सत्ता और क्या विपक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की व्यवस्था के प्रश्न परिसर के बाहर बिखर गए। कई मुंह वाले नेताओं को सिर्फ कुछ कर दिखाना है, इसलिए हमने देखा राजनीति के कितने दरवाजे हो सकते हैं। यहां जनता की वकालत नहीं, प्रदेश के पैमाने नहीं, यहां सरदारियां हैं, कुछ पगडि ?ां और तैयारियां हैं। बेचारे पेंशनर्स अपनी उम्र के खाके-पेंशन के फाके लिए, जोरावर स्टेडियम से बेदखल, पुलिस ग्राऊंड की विशालता में गूंज पैदा करते रहे। बहुत दूर नहीं हो सकता सरकार का दिल और इसीलिए काबिल बनने से पहले बेरोजगारों के सपने-अधिकारों के नथुने फूलते रहे। यह सब प्रदेश के लिए हो रहा है या हम बेहतर विकल्पों की तुलना में चुनाव-दर-चुनाव, आंदोलन से तर-ब-तर आजमाइश कर रहे हैं। पेंशनरों के आंदोलन से बड़ा संघर्ष क्या सत्ता बनाम विपक्ष है, जो विधानसभा परिसर की दीवारों के बाहर बर्र का छत्ता बना नजर आया। नजर आया कि विधायक होने का अब अर्थ क्या है। नजर आया कि विपक्ष नारे लगाएगा, तो सामने सत्ताधारी वंश भी उतर आएगा। सदन के बाहर तमाशा अच्छा है या भीतर किसी मंत्री का भाषण अच्छा है। कम से कम राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के भाष्य संदर्भ, विपक्षी टुकडि ?ों को आंदोलन उठाने की सहूलियत दे गए। कई बार लगता है कि राजनीतिक दूध में मक्खियां ही मक्खियां हैं, किस किस को निकालोगे, यहां हाथ गिरेबां तक नहीं पहुंचता। किसने क्या मांगा यह तेरी तकदीर, तू हिमाचल है तंगदिल शरीर। हर बार और हर सरकार में हिमाचल का संतुलन होता नहीं, इन बातों में खुशामद के सिवा कुछ होता नहीं। खैर दो दिन विराम के बाद, क्या चैन लौट आएगा या वर्तमान सरकार के खिलाफ भाजपा तीन साल का रोष दिखा पाएगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी का जश्न नए प्रदेशाध्यक्ष की संगत में अपनी विसंगतियों की पापड़ बेलेगा या हृदय में बसे अपने-अपने राम की तलाशी में मजदूरी करेगा। जो भी हो तपोवन में शीतकालीन सत्र का कथानक हर बार एक नया नाटक पैदा करता है। बदले हैं कई विधायक और उनके सवालों का असर जोरदार होता है। जो विधायक बजीर रामसिंह पठानिया को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने की मांग करते हैं, उनके इतिहास को सलाम। जो आवारा पशुओं की शिनाख्त करते हैं, उनके सुझावों को साधुवाद। कई बार आश्चर्य होता है कि पूरा विधानसभा सत्र यूं तो बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े इरादे सुनता है, लेकिन प्रदेश की हैसियत में फर्क नहीं पड़ता। शुक्रगुजार है हिमाचल कि घायल कर देने वाली टिप्पणियों को कार्यवाही से हटा देने का माद्दा अभी शेष है, वरना सियासत ने लोकतांत्रिक परंपराओं की कसौटियां बदल डाली हैं। मंत्रियों ने कहा है कि अवैध खनन पर प्रहार होगा, हर अस्पताल के इलाज में अच्छा व्यवहार होगा। दक्ष डाक्टर आएंगे, नलके में पूरा पानी आएगा, गांव के बच्चे मिट्टी से नहीं-स्कूल के मैदान में खेलेंगे। बहुत सरोवर हैं सत्र की गहराई में, बशर्ते कोई डूब के देखे। विधानसभा सत्र के मध्यांतर में हम यह नहीं कह सकते कि पूरी कहानी कौन बेहतर लिखेगा, लेकिन अपने-अपने एहसास को जीते विधायकों की दिहाड़ी का मंतव्य भूखा किसान, दिहाड़ीदार और बेरोजगार जरूर पूछेगा। इस बीच पेपर लीक कानून के पंजे सख्त करने की अभिलाषा में सुक्खू सरकार सफल हो गई। हिमाचल के भविष्य की तपती रेत पर पेपर लीक करने वालों के खिलाफ अब रास्ता कठिन हो गया है, फिर भी सरकार ने चिट्टे पर ~~प्रहार करने के लिए पहली दिसंबर को महाभियान के दूसरे चरण के प्रति~~ प्रतिबद्धता का अलख जगाया है। बहरहाल, सरकार शीतकालीन सत्र के पार अपनी उपलब्धियों और संकल्पों की एक नई इबारत लिखने के लिए मंडी में तीन साल पूरे कर रही है। हिमाचल की आर्थिक चुनौतियों के बीच, विकास के बीज बोना या व्यवस्था परिवर्तन के सपने संजोना आसान नहीं, फिर भी विपक्ष जो सवाल शीतकालीन सत्र में छोड़ जाएगा, उन पर मंडी के संबोधन जरूर जवाब देंगे।

भारत में चार नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन चार संहिताओं में 'कोड ऑन वेजेज 2019', 'इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020', 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020' और 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020' शामिल हैं। श्रम सुधारों का यह नया ढांचा भारत के आर्थिक, डिजिटल और औद्योगिक भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मॉडल है। यह सुधार न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान है बल्कि आने वाले दशकों में रोजगार परिदृश्य को स्थिरता, पारदर्शिता और सशक्तिकरण की नई दिशा देगा। नए कानूनों के लागू हो जाने से भारतवर्ष की उत्पादन क्षमता, रोजगार गुणवत्ता, औद्योगिक सामंजस्य और वैश्विक स्पर्धा में वृद्धि की पूर्ण संभावना दिखाई पड़ रही है। कह सकते हैं कि देश ने अपनी श्रम नियमावली को फिर से लिखा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत आधार प्रदान करने में नए चार श्रम कोड कारगर भूमिका अदा करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अगर नए कानून जमीन पर उतरने में सफल रहे तो श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। इसी का विश्लेषण करता *आजकल* का यह खास अंक...

नए श्रम कानूनों से बदलेगी तस्वीर

विश्लेषण

रोहित माहेश्वरी

स्वतंत्र पत्रकार

सालों से इंतजार किए जा रहे चार नए श्रम कानूनों को बीती 21 नवंबर को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन चार संहिताओं में 'कोड ऑन वेजेज 2019', 'इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020', 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020' और 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020' शामिल हैं। 29 श्रम कानूनों को खत्म करके चार नए कानून पेश किए गए हैं, जो सभी तरह के कर्मचारियों को कवर करते हैं। इस कानून के तहत सैलरी, अनिवार्य नियुक्ति पत्र, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेच्युटी और समान काम की समान सैलरी आदि जैसे बदलाव हुए हैं। इसमें दो राय नहीं कि नए श्रम कानून लागू करना देश के श्रम परिदृश्य में एक नए दौर में प्रवेश करने जैसा है। केंद्र सरकार ने चारों श्रम कानून मसलन वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्य स्थितियों को अधिसूचित किया है। दावा किया जा रहा है कि इससे अनुपालन सरल बनेगा, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार होगा और ये कदम श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूती देगा। केंद्र सरकार की इस कदम से कर्मचारियों को समय पर वेतन, औपचारिक नियुक्ति पत्र देने, न्यूनतम वेतन की गारंटी और वार्षिक स्वास्थ्य जांच का वादा किया गया है।

इसमें दो राय नहीं कि नए श्रम कानून लागू करना देश के श्रम परिदृश्य में एक नए दौर में प्रवेश करने जैसा है। केंद्र सरकार ने चारों श्रम कानून मसलन वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्य स्थितियों को अधिसूचित किया है। दावा किया जा रहा है कि ये कदम श्रमिकों की सुरक्षा को मजबूती देगा। निस्संदेह, देश ने अपनी श्रम नियमावली को फिर से लिखा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव आने में अभी कुछ वक्त लगेगा। अगर नए कानून जमीन पर उतरने में सफल रहे तो श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।

सैलरी का दायरा बढ़ेगा

नए कानूनों के तहत कर्मचारियों को समय पर सैलरी दी जाएगी। देशभर में मिनिमम सैलरी का दायरा बढ़ेगा यानी कि बाकी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि कोई भी सैलरी इतनी कम नहीं हो कि कर्मचारियों का जीवन-यापन कठिन हो। नए कानून के तहत अब ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि 1 साल की सर्विस पर ही ग्रेच्युटी दी जाएगी। यह ग्रेच्युटी फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिलेगी। इन सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने का किया गया है। इसके अलावा गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स ओर एग्रीगेटर्स को इन कानूनों के तहत पहली बार डिफाइन किया गया है। इन्हें भी आधार-लिंक्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से वेलफेयर बेनिफिट्स दिया जाएगा, जिसमें पीएफ से लेकर पेंशन तक का लाभ शामिल होगा। 40 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को सालाना फ्री हेल्थ चेकअप दिया जाएगा। केंद्र सरकार मजदूरों की बेहतर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मानदंड बनाएगी।

महिला कर्मियों का हित

नए कानूनों के तहत महिलाएं सभी जगहों पर काम कर सकती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग, भारी मशीनरी और खतरनाक काम शामिल हैं, जिससे सभी के लिए रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित होंगे। हर साइट पर ऑन-साइट सेफ्टी मॉनिटरिंग के लिए जरूरी सेफ्टी कमेटी और खतरनाक रसायनों की सुरक्षित हैंडलिंग पक्का करना है। वहीं फिक्स्ड-टर्म एम्प्लॉई (एफटीई) से रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा, स्थाया कमचारा क बराबर फायद जस कानूनी सुरक्षा पक्की होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को समाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। महिला-पुरूष भेदभाव कानूनी तौर पर नकार दिया गया है। महिला हो या पुरुष समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में भी काम करने का अधिकार होगा। सभी कामगारों के लिए मिनिमम सैलरी की गारंटी होगी। सभी तरह के कर्मचारियों को ऑफर लेटर देना होगा, जिससे सामाजिक सुरक्षा, रोजगार विवरण और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। छुट्टी के दौरान मजदूरी देना अनिवार्य किया गया है। मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से तय की गई फ्लोर वेज के हिसाब से वेतन दिया जाएगा।

ग्रेच्युटी व प्रोविडेंट फंड बेहतर

सभी प्रवासी कामगारों (डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर-बेस्ड और खुद माइग्रेटेड) को बराबर वेतन, वेलफेयर बेनिफिट और पीडीएस पोर्टेबिलिटी का लाभ दिया जाएगा। कामगार 3 साल तक लंबित बकाय के निपटारे के लिए दावा कर सकते हैं। सभी डॉक वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और बीमा के लाभ तय कर दिया गया है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या अस्थायी कर्मचारी। जानकारों के मुताबिक नए लेबर कोड्स 'कोड ऑन वेजेज' और 'सोशल सिक्यारिटा' क तहत 'वजज' (सलरा) का परिभाषा को एक जैसा बनाते हैं। इससे ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड बेहतर होगा, लेकिन अगर कंपनियां खर्च कम करने के लिए अलाउंस घटाती हैं, तो हाथ में आने वाली सैलरी कम हो सकती है। श्रम क्षेत्र के जानकारों के अनुसार, अब 'वेजेज' में बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस यानी डीए और रिटेनिंग अलाउंस यानी आरए शामिल होंगे। कुल कमाई का 50 प्रतिशत (या सरकार द्वारा तय की गई कोई और प्रतिशत राशि) 'वेजेज' में जोड़ा जाएगा। इससे ग्रेच्युटी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना में एकरूपता आएगी। पहले कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखकर बाकी पैसा अलग-अलग भत्तों के रूप में दे देती थीं। इससे पीएफ और ग्रेच्युटी में उनका योगदान कम होता था। लेकिन अब सरकार ने नियम बना दिया है कि आपकी कुल सैलरी यानी सीटीसी का कम से कम आधा हिस्सा बेसिक सैलरी होना चाहिए। इससे आपकी रिटायरमेंट सेविंग्स तो बढ़ेंगी, लेकिन हर महीने हाथ में आने वाले पैसे थोड़े कम हो सकते हैं। यह एक तरह से आपकी भविष्य की सुरक्षा के लिए अच्छा कदम है, भले ही अभी थोड़ा जेब पर भारी पड़े। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि श्रम सुधारों के कई प्रावधान, लंबे समय से अपेक्षित प्रगति का संकेत देते हैं।

जमीनी स्तर पर हो बदलाव

सभी क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन का सार्वभौमिक वैधानिक अधिकार, अनिवार्य लिखित नौकरी अनुबंध, निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिये बेहतर ग्रेच्युटी तक पहुंच और स्वास्थ्य व सुरक्षा पर स्पष्ट मानदंड, औपचारिक प्रावधानों और पारदर्शिता की दिशा में बदलाव को रेखांकित करते हैं। निश्चित रूप से सामाजिक-सुरक्षा ढांचे के भीतर गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को मान्यता देना शायद सबसे बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन माना जा सकता है। निश्चय ही, ये देश के लाखों कामगारों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। निस्संदेह, देश ने अपनी श्रम नियमावली को फिर से लिखा है। लेकिन जमाना स्तर पर ठास बदलाव आन म अभा कुछ वक्त लगेगा। अगर नए कानून जमीन पर उतरने में सफल रहे तो श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।

श्रम संसार की तस्वीर बदलने वाली गारंटी

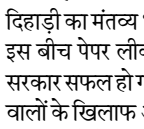

राष्ट्र-चिंतन

आचार्य श्रीहरि

स्वतंत्र पत्रकार

श्रमेव जयते। श्रम की प्रधानता और समृद्धि के बिना जीवंत राष्ट्र की परिकल्पना नहीं हो सकती है। श्रम की कसौटी पर निर्माण और विकास की परिकल्पना बनती है। इसलिए श्रम की महत्ता और अनिवार्यता को अस्वीकार करना मुश्किल है। इनकी उपेक्षा और इन पर उदासीनता अस्वीकार है। सरकार की ही नहीं, बल्कि नियोक्ता और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी भी स्वस्थ और समृद्ध श्रम संसाद की बनती है। यह अच्छी और स्वागतपूर्ण कदम है कि नरेन्द्र मोदी ने मजदूरों की तस्वीर बदलने की गारंटी दी है, उनकी आजीविका के अधिकार को सशक्त बनाया है। उनके होने वाले शोषण और उत्पीड़न पर रोक लगाने की व्यवस्था की है और भेदभाव की नीतियों को समाप्त करने की घोषणा की है, यानी कि श्रमेव जयते। इस निमित नरेन्द्र मोदी की सरकार ने चार नए श्रम संहिताओं की घोषणा की है। इन श्रम संहिताओं की घोषणा से लगभग 30 साल के श्रम काले कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, जो काफी समय से प्रस्तावित और प्रत्याशित थे। चार नये श्रम संहिताओं को इस प्रकार से जानिये। पहला वेज कोड 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेल्फी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 में परिवर्तन कर दिया गया है। इससे मजदूरों के वेतन और सुरक्षा अधिकारों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा और लाभकारी भी होगा। नए श्रम संहिताओं में मजदूरों के सभी प्रकार के अधिकारों और कल्याण की भावनाओं को निहित किया गया है। औद्योगिकीकरण और कारपोरेटिवकरण तथा रोजगार और श्रम के नये आयामों के उद्भव और विकास के कारण मजदूरों के सामने विकट समस्या उत्पन्न हो गयी थी, निवेशकों के सामने भी बहुत बडी समस्या थी, पूर्व की श्रम संहिताएं अस्पष्ट थी और विसंगतियों से भरी पड़ी थी, नियोक्ता और श्रमिकों के बीच अविश्वास उत्पन्न करती थी, अधिकारों को लेकर संहिताएं स्पष्ट भी नहीं थी। न्यूनतम वेतनमान में हीलाहवाली थी, असमानता थी और शोषण युक्त था। नयी आर्थिक नीतियों के लागू होने से सर्वाधिक शोषण के शिकार मजदूर थे और उनके हित हाशिये पर थे, उनके आंदोलन करने के अधिकार और कर्तव्य पर नियोक्ता, पुलिस और प्रशासन की टेढी नजर रहने लगी थी। भारत की ये श्रम संहिताएं विश्व की अन्य संहिताओं के अनुपात में कितनी लाभकारी हैं, कितनी सहयोगी हैं और कितनी कल्याणकारी हैं? नई श्रमिक संहिताएं श्रमिकों के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए बेमिसाल तो हैं पर नियोक्ताओं और सेवादाता कंपनियों के बीच भी श्रम कानूनों को लेकर विश्वास उत्पन्न करने की आवश्यकता है। उम्मीद है कि नरेन्द्र मोदी सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विश्वास और संतुलन बनाने की भूमिका निभाएगी।

इन श्रम संहिताओं की घोषणा से लगभग 30 साल के श्रम काले कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, जो काफी समय से प्रस्तावित और प्रत्याशित थे।

भारत में नए लेबर कोड : श्रमिक अधिकारों का नया अध्याय

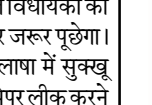

रणनीति

सुनील कुमार महला

स्वतंत्र पत्रकार

केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 शुक्रवार को कार्य परिस्थितियों में बड़े बदलाव का कदम उठाते हुए देश में नई श्रम संहिता (लेबर कोड) लागू कर दी। यह वाकई काबिले-तारीफ है कि निजी एवं असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों के लिए उपयोगी इस नए लेवर कोड में अनिवार्य नियुक्ति-पत्र, न्यूनतम और समय पर वेतन की गारंटी और एक साल में ही ग्रेच्युटी भुगतान की व्यवस्था की गई है, वहीं सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ईएसआइसी सुविधा और 40 साल की सेवा के बाद अनिवार्य स्वास्थ्य जांच जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। बता दें कि ईएसआईसी भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व और रोजगार से जुड़ी अन्य आपात स्थितियों में आर्थिक तथा चिकित्सीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद इसे सबसे बड़ा रिफॉर्म बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कृषकों को मजबूत बनाने वाला है। इनसे एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होगा, जो भविष्य में कामगारों के हकों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा, साथ ही विकसित भारत की यात्रा को भी तेज गति मिलेगी।' कितनी अच्छी बात है कि नए लेबर कोड में महिलाओं के लिए खास सुविधाएं जोड़ी गई हैं, वहीं खतरनाक व जोखिम वाले उद्योगों, गिग वर्कर्स और आइटी क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए भी विशेष उपाय किए गए हैं। आज के समय में ओला-उबर के ड्राइवर, स्विगी-जोमैटो, ब्लिंकिट ,अमेजन के डिलीवरी पार्टनर, फ्रीलांसर (कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, वेब डेवलपर, डिजिटल मार्केटर आदि), डिज़ाइनर, या अर्बन कंपनी जैसी सर्विस देने वाले लोग गिग वर्कर्स के रूप में जाने जाते हैं। यह काम लचीला होता है, इसलिए लोग अपनी सुविधा अनुसार समय तय कर सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसमें स्थायी नौकरी जैसे लाभ जैसे पीएफ, पेंशन, मेडिकल सुरक्षा अक्सर नहीं मिलते। यही कारण है कि गिग वर्कर्स को असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है।

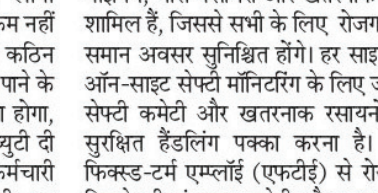

यदि पारदर्शिता से काम हो तो यह कोड अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सच तो यह है कि गिग वर्कर्स, खनन श्रमिकों और टैक्सटाइल श्रमिकों के लिए नए लेबर कोड में विशेष इंतज़ाम किए गए हैं,जो सराहनीय हैं। वास्तव में अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआइसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिल सकेंगे। इतना ही नहीं, खनन श्रमिकों के क्रम में आवागमन दुर्घटना पर मुआवजा, खान में सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों का ध्यान, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही साथ काम के घंटों की सीमा प्रतिदिन 8 से 12 घंटे, तथा प्रति सप्ताह 48 घंटे तय की गई है। टैक्सटाइल श्रमिकों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मसलन, ठेकेदार कर्मियों को समान वेतन, कल्याणकारी लाभ, बकाया निपटान के लिए तीन साल की अवधि, तथा ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान जैसी व्यवस्थाएं नये लेबर कोड में की गई हैं। नए लेबर कोड में महिलाओं के लिए खास सुविधाओं में क्रमशः लिंग भेद निषेध, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिलाओं को सहमति व जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि पाली में तथा सभी प्रकार के काम की अनुमति, शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जरूरी, महिला कर्मचारी के परिवार की परिभाषा में सास-ससुर को शामिल करना, 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, क्रैच व वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के साथ ही साथ 3500 रुपये का मेडिकल बोनस दिए जाने की व्यवस्थाएं भी की गईं हैं। वास्तव में लेबर कोड में विभिन्न सुधारों से कामगारों को निश्चित ही लाभ हो सकेगा। कुल मिलाकर, श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए नए लेबर कोड की आवश्यकता महसूस की गई। अब नए लेबर कोड से श्रमिकों के दिन बदलेंगे। हालांकि, इनकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि सरकार और उद्योग पारदर्शिता से काम करें तो यह कोड भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

रोजगार, सुरक्षा और सम्मान की दिशा में ऐतिहासिक पहल

श्रम कानून

रवि शंकर

वरिष्ठ पत्रकार

एक लंबे इंतजार के बाद देश के श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, जो कई तरह से ऐतिहासिक है। इसकी मांग दशकों से की जा रही थी। पुराने 29 श्रम कानूनों को अब इतिहास बनाते हुए उनकी जगह 21 नवंबर से देश में चार नए श्रम कोड लागू हो गए हैं। इसे श्रम सुधारों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

ये कोड हैं- वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति संहिता 2020। इनका मकसद कामगारों को सुरक्षित काम, समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा देना है। संसद ने ये चार लेबर कोड लगभग पांच साल पहले पारित कर दिए थे। लेकिन इन्हें अब जाकर लागू किया गया है। अब पूरे देश में संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रम कानून एक जैसे होंगे। इन संहिताओं का सबसे बड़ा उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण को मजबूत बनाना, उद्योगों को सुगम कार्य-परिस्थिति देना, डिजिटल कार्य संस्कृति को औपचारिक मान्यता देना और गिग-प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे उभरते श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इससे भारत की उत्पादन क्षमता, रोजगार गुणवत्ता, औद्योगिक सामंजस्य और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। बहरहाल, इन कानूनों को लागू करते हुए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ऐसा मानना है कि ये बदलाव देश में रोजगार और औद्योगिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। नए श्रम कानूनों से देश के करीब 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज भी मिलेगी।

पहले देश में लागू श्रम कानून 1930-1950 के बीच के बनाए गए थे। उन कानूनों में श्रमिकों के आर्थिक हितों का ध्यान नहीं रखा गया था। लेकिन नए कानून इन बातों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि, कई मजदूर संगठनों का आरोप है कि ये कोड कंपनी मालिकों को पहले से कहीं अधिक अधिकार देते हैं। खासकर छोटी और असंगठित कंपनियों में कामगारों का शोषण बढ़ेगा। दावा किया जा रहा है कि यह अद्भुत संतुलन वाला कानून है, जिससे मजदूरों और कर्मचारियों को भी फायदा होगा तो उद्योग समूहों को भी लाभ होगा। सवाल है कि जब दोनों के लिए फायदे वाला कानून है तो इसे लागू करने में सरकार को छह साल क्यों लग गए? दूसरा सवाल यह है कि अगर ये कानून मजदूरों के हित में हैं तो देश के ज्यादातर बड़े मजदूर संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में संसद में पास करने से लेकर इनके नियम बना कर इन्हें लागू करने तक जब भी इन कानूनों की बात होती है तो दावा किया जाता है कि इनसे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिलेगी, समय पर उचित वेतन मिलेगा तो दूसरी ओर कंपनियों को एक ऐसा सरल ढांचा मिलेगा, जिसके अनुपालन में उनको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यह सिर्फ सदिच्छा है। वास्तव में इसका कितना लाभ मिलता है यह इन कानूनों के अनुपालन के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि मजदूरों के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सीमित कर दिया गया है। नए कानून में प्रावधान है कि हड़ताल से 60 दिन यानी दो महीने पहले नोटिस देना होगा।

वास्तव में श्रम कानून का कितना लाभ मिलता है यह इन कानूनों के अनुपालन के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात साफ है कि मजदूरों के हड़ताल या विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सीमित कर दिया गया है।

अगर कर्मचारी या मजदूर अपनी किसी समस्या के लिए तत्काल विरोध प्रदर्शन या हड़ताल नहीं कर पाएंगे तो उनकी समस्या को निराकरण कैसे होगा? वहीं सामाजिक सुरक्षा वाले तीसरे कानून में गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड की बात कही गई है। लेकिन यह फंड कैसे बनेगा? कंपनियां कितना योगदान करेंगी और मजदूरों को उसका लाभ कैसे मिलेगा, इस बारे में बहुत स्पष्टता नहीं है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा वाले चौथे कानून में रोज के काम के घंटे का विस्तार 12 घंटे तक कर दिया है। असल में नए श्रम कानून जैसा कि हमेशा होता है उद्योग समूहों और निवेशकों के हितों को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना और उद्योग समूहों का विस्तार करना है। सभी सरकारें मानती रही हैं कि उद्योगों का विकास होगा, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और संपन्नता आएगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर कानून शोषण और गैर बराबरी को बढ़ाता है। ये कानून भी अपवाद नहीं हैं। इनमें भी फिक्स्ड टर्म नौकरी पर जोर दिया गया है, जिसका मतलब है कि स्थायी नौकरियां कम होंगी और ठेके पर काम ज्यादा उपलब्ध होगा। इससे सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी नहीं कम होगी। इसी तरह कंपनियां नियमों का कैसे अनुपालन करती हैं उसकी जांच और निगरानी की व्यवस्था कमजोर कर दी गई है। कुछ पहलुओं को छोड़ दिया जाए तो नई श्रम संहिताएं आवश्यक संतुलन साधने में सफल दिखती हैं। ये बदलाव सिर्फ आज के कामगारों के लिए नहीं, आने वाले समय में काम की दुनिया बदलने की चुनौती के लिए हैं। दरअसल, श्रम सुधारों का यह नया ढ़ांचा भारत के आर्थिक, डिजिटल और औद्योगिक भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मॉडल है। यह सुधार न केवल वर्तमान चुनौतियों का समाधान है बल्कि आने वाले दशकों में रोजगार परिदृश्य को स्थिरता, पारदर्शिता और सशक्तिकरण की नई दिशा देगा।

मौसम

अधिकतम तापमान 42.c

न्यूनतम तापमान 29.c

बाजार

सोना 7,177/ g

चांदी 96/ g

सेंसेक्स 82,530.74

निफ्टी 25,062.10

खबर संक्षेप

शादी में फायरिंग, दूल्हे की मौसी, दोस्त की मौत

लुधियाना। यहां शादी समारोह के दौरान गोलियां चलने के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। पक्खोवाल रोड स्थित बाथ कैस्टल पैलेस में शनिवार रात को शादी में उस समय भगदड़ मच गई। वहां 2 गैंगस्टर गुटों में रंजिशन ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। दोनों तरफ से 50 के करीब राउंड फायर किए गए। दूल्हे की मौसी और दोस्त की मौत हो गई। एक घायल हो गया।

चमोली में भूकंप के झटकों से दहशत

चमोली। उत्तराखंड में रविवार को एक बार फिर धरली डोली। चमोली के नारायणबगड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे लोगों में दहशत फैल गई और लोग घरों भूकंप के झटके 10 बजकर 27मिनट पर, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली और देवाल में महसूस हुए। भूकंप

दहशत फैल गई और लोग घरों भूकंप के झटके 10 बजकर 27मिनट पर, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, थराली और देवाल में महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। इस भूकंप में किसी तरह की नुकसान की सूचना नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' में कई विषयों पर की चर्चा

उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म तेजी से बन रहा पसंदीदा विकल्प, पर्यटक हो रहे आकर्षित

कार्यक्रम के 128वें एपिसोड में लोगों से लेकर सेना- नौसेना का भी किया जिक्र

नई दिल्ली,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के 128वें एपिसोड में उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म पर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेयारा जैसी जगहें तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और देशभर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। दुनिया के कई देशों ने विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बना लिया है, जहां स्कीइंग, स्नो-बोर्डिंग, आइस क्लाइंबिंग, स्नो ट्रेकिंग और फैमिली स्नो पार्क विशेष आकर्षण होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भी विंटर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं।

उन्होंने बताया कि ऊंचे पर्वत, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और एडवेंचर गतिविधियां भारत को इस क्षेत्र में बड़ी पहचान दिला सकती हैं। उन्होंने विशेष उदाहरण देते हुए कहा कि पिथौरागढ़ जिले में 14 हजार फीट से ज्यादा ऊंचाई पर पहली बार हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन आयोजित की गई, जिसमें 18 राज्यों के 750 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी फाइल फोटो

देशभर के खिलाड़ी और एडवेंचर प्रेमी उत्साहित

पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए देशभर के खिलाड़ी और एडवेंचर प्रेमी उत्साहित हैं। स्कीइंग, स्नो-बोर्डिंग और बर्फ से जुड़े अन्य खेलों की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और होमस्टे नीति को मजबूत कर रही है।

लोकप्रिय जगहों का भी किया बखान

आदि कैलाश परिक्रमा में लोगों का बढ़ा उत्साह

प्रधानमंत्री ने 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का भी जिक्र किया, जो कड़कड़ाती ठंड में सुबह 5 बजे शुरू हुई। उन्होंने कहा कि इतनी ठंड के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने कहा कि आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों की संख्या पहले 2हजार थी, जो अब बढ़कर 30 हजार से अधिक हो गई है।

'वेड इन इंडिया' अभियान को मिला बढ़ावा

प्रधानमंत्री ने सर्दियों में बढ़ती डेस्टिनेशन वेडिंग्स की लोकप्रियता पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 'वेड इन इंडिया' अभियान के साथ पहाड़ों पर होने वाली शादियों में तेजी आई है। गंगा किनारे होने वाली शादियां भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं।

नमो घाट पर काशी-तमिल संगमम हो रहा

पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर काशी-तमिल संगमम के चौथे संस्करण की शुरुआत हो रही है। यह उन सभी लोगों के एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, जिन्हें तमिल भाषा से प्यार है। काशीवासीउत्साह से भाई-बहनों का स्वागत करने कोॉ उत्सुक हैं।

'माहे' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया

मुंबई में आईएनएस 'माहे' को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कुछ लोगों के बीच इसके स्वदेशी डिजाइन को लेकर खूब चर्चा रही। वहीं, पुडुचेरी और मालाबार तटीय इलाकों के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए। 4 को हम नौसेना दिवस मनाने जा रहे हैं।

'वोकल फॉर लोकल' को देशवासियों ने अपनाया

पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने की देशवासियों से अपील की और बताया कि हाल ही में जी20 सम्मेलन में उन्होंने दुनियाभर के नेताओं को जो उपहार दिए, वे भारतीय कारीगरों ने तैयार किए थे। पीएम मोदी ने कहा कि 'मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल की भावना को देशवासियों ने अपना लिया है।

सहनशक्ति की परीक्षा वाले खेलों में तेजी

प्रधानमंत्री ने देश में एंड्युरेंस स्पोर्ट्स यानी सहनशक्ति की परीक्षा लेने वाले खेलों की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता पर बात की। उन्होंने कहा देश में एंड्युरेंस स्पोर्ट्स की संस्कृति तेजी से उभर रही है। इससे मतलब ऐसी गतिविधियों से है, जिनमें इंसानी क्षमता की परख होती है। देशभर में हर महीने 1500 से ज्यादा एंड्युरेंस स्पोर्ट्स का आयोजन होता है।

बीएलओ को बढ़ा मानदेय नहीं दिया

चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को दिया भुगतान करने का आदेश

नई दिल्ली,

चुनाव आयोग ने बीते दिनों बीएलओ के मानदेय को बढ़ाने का आदेश जारी किया था। ईसी के आदेश के बावजूद बंगाल की टीएमसी सरकार ने बीएलओ और निर्वाचन आयोग के अन्य अधिकारियों को बढ़े हुए मानदेय का भुगतान नहीं किया। इसे लेकर अब चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई है। ईसी नेअगस्त में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें लिखा 'शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र के आधार हैं। मतदाता सूची तैयार करने वाली मशीनरी में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, बीएलओ सुपरवाइजर और बीएलओ शामिल होते हैं। ईसी ने बीएलओ और अन्य अधिकारियों का सालाना मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है।

कर्मियों को जल्द भुगतान किया जाए

2015 से बीएलओ को सालाना मानदेय 6 हजार था, जिसे बढ़ाकर 12 हजार कर दिया गया है। वहीं मतदाता सूची के लिए पहले बीएलओ को एक हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 हजार कर दिया गया है। बीएलओ सुपरवाइजर को पहले 12 हजार का मानदेय मिलता था, जो अब बढ़ाकर 18 हजार कर दिया गया है। वहीं इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी को 30 हजार और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारी को 25 हजार का सालाना मानदेय मिलेगा। पहले इन अधिकारियों को कोई मानदेय नहीं मिलता था। ईसी ने कहा है कि हमने टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल से कहा कि बीएलओ के बढ़ाए गए मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

लखनऊ में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला

निर्मला नाम से फर्जी आधार बनवाया और यहां शादी भी कर ली

लखनऊ। लखनऊ की एटीएस ने नरगिस अख्तर उर्फ निर्मला देवी उर्फ जैस्मिन को ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया है। अख्तर का निर्मला देवी के नाम से भारतीय दस्तावेज बनवाने वाला उसका पति हरिओम आनंद भी गिरफ्त में है। अख्तर जलीकोठी की रहने वाली है। वह 2010 में टूरिस्ट वीजा पर भारत आई थी। उसने पहला फर्जी आधार कार्ड पश्चिम बंगाल में जेसिका विश्वास के नाम बनवाया था। 2022 में हरिओम ने लखनऊ से निर्मला के नाम से फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाए। इसी साल दोनों ने शादी की थी।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा

लोकतांत्रिक ढांचे को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया, इसे 'चारपाई' के समान बताया

इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी के उद्घाटन पर कहा

नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने हरियाणा में एपी जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका की असली शक्ति पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक ढांचे को बेहद सरल और प्रभावी तरीके से समझाया। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की तुलना एक चारपाई से करते हुए कहा कि हमारा लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत लकड़ी के फ्रेम और टिकाऊ रस्सियों की तरह है जो एक तरफ स्थिर है, तो दूसरी तरफ परिस्थितियों के अनुसार लचीला भी।

हरियाणा में एपी जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजन

संबोधन के दौरान सीजेआई सूर्यकांत

केशवानंद के फैसले पर भी की बात

केशवानंद के फैसले पर बात करते हुए सीजेआई ने कहा कि जब यह ऐतिहासिक सुनवाई चल रही थी, उस समय भारत संवैधानिक जीवन के 23वें वर्ष में था। देश आदर्शवाद तथा शक्तियों के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया सीख रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के 13 जज भी रहे शामिल

इस सम्मेलन में एक विशेष सत्र भी रखा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने मंच पर मौजूद रहते हुए केशवानंद भारती केस की ऐतिहासिक बहस को दोबारा रीक्रिएट किया। इस रिक्रिएशन में कई वरिष्ठ वकीलों ने भी हिस्सा लिया। अटॉर्नी जनरल की भूमिका वेंकटेश मणि ने निभाई, जबकि वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने भारत सरकार और केरल सरकार का पक्ष प्रस्तुत किया।

तेलंगाना हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद पर यह फैसला दिया

इस उम्र में तलाक लेकर कोई फायदा नहीं, 34 साल पुरानी शादी तोड़ने से किया साफ इनकार

पति और पत्नी दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ दायर की थी अपील

नई दिल्ली,

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अनोखे और लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद पर ऐसा फैसला दिया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया। अदालत ने साफ कहा कि इस उम्र में तलाक लेकर कोई फायदा नहीं। और यही बात अदालत के फैसले का आधार भी बनी। 34 साल पुरानी शादी को टूटने से रोकते हुए कोर्ट ने माना कि अब रिश्ते को कानूनी रूप से खत्म करना व्यावहारिक समाधान नहीं है।

17 साल तक चली कानूनी लड़ाई

इस केस में खास बात यह थी कि पति और पत्नी दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ अपील दायर की थी। 17 साल तक चली कानूनी लड़ाई, कई सुनवाई, पति की गुमशुदा स्थिति और बच्चों के वयस्क हो जाने के बाद अदालत ने महसूस किया कि तलाक का कोई ठोस उद्देश्य अब बचा ही नहीं है। इसलिए कोर्ट ने तलाक ही नहीं बल्कि पहले दिए गए ज्यूडिशियल सेपरेशन के आदेश को भी रद्द कर दिया। यह मामला 2008 में शुरू हुआ था, जब पति ने 1991 में हुई अपनी शादी को खत्म करने के लिए याचिका दायर की। पति पेशे से सिविल इंजीनियर ह। उनका आरोप था कि पत्नी लगातार उन पर बेवजह शक करती थी।

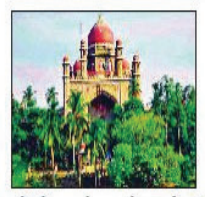

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र० //अ-20(3)/2025-26
ईश्तेहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका आशा सिंह हिशिकर पत्नी राहुल हिशिंकर आ० स्व० चक्रधारी सिंह निवासी शीतला वार्ड सत्तीपारा अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० मुख्तारधारक हरी सिंह आ० स्व० बिहारी राम सिंह निवासी पम्पापुर थाना व तहसील दरिमा जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर-9 मोहल्ला शीतला वार्ड नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 3447/2 रकबा 0.21 एकड़ भूमि को अनावेदक/केता स्निग्धा अग्रवाल पत्नी आशीष अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी बनभौरी स्टोर पुराना बस स्टैण्ड ब्रम्हपारा अम्बिकापुर, थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग०, कोमल अग्रवाल पत्नी नवीन कुमार अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी हाउस नम्बर 105 पुराना बस स्टैण्ड रोड बनभौरी स्टोर वार्ड कमांक 34 अम्बिकापुर थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के पास बिकय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 17/12/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है।नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांक 26/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा सेजारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र० //अ-20(3)/2024-25
ईश्तेहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक प्रीतम चन्द्र अग्रवाल आ० नान्हू राम अग्रवाल जाति अग्रवाल आयु 66 वर्ष निवासी रायगढ़ रोड पत्थलगांव जशपुर छ०ग० के द्वारा अपने स्वामित्व की मोहल्ला खरसिया रोड नगर अम्बिकापुर शीट नम्बर 8 स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 2824/9 रकबा 0.014 हे0 अर्थात 1530 वर्गफीट भूमि मे से रकबा 15 60 = 900 वर्गफीट भूमि को अनावेदक/केता रानी अग्रवाल पत्नी मनीष अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी महामाया रोड थाना व तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ०ग० के पास बिकय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 17/12/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः 26/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ०ग०)
//सार्वजनिक उद्घोषणा/ईश्तहार//
क्रमांक/1595/वाचक-2/2025
सूरजपुर दिनांक 20/11/2025

सर्व साधारण ग्रामवासी /नगरवासी ग्राम केतका प . ह.न. तहसील जिला सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सुचित किया जाता है कि आवेदक संगीत सिंह पिता स्व. अवतार सिंह जाती गोड़ निवासी ग्राम केतका पोस्ट केतका थाना सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर ने अपने पुत्र/पुत्री ससुर रामद ?याल

पिता रामचरण जन्म मृत्यु तिथि19/06/2022 स्थान केतका के जन्म मृत्यु पत्र हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है। अतः इस न्यायालय में जिस व्यक्ति को कोई दावा/आपत्ति आक्षेप हो तो वे स्वंय /2025 दिन 5./12/2025. को उपस्थित अथवा अपने अभिभावक द्वारा इस न्यायालय में दिनांक होकर दावा /आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।बाद में प्राप्त दावा / आपत्ति/आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 20/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

तहसीलदार
सूरजपुर

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष
ग्राम
प.ह.न.
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक लालजी सिंह आ रामसाय निवासी ग्राम कुरीडीह प.ह.न.04 रा.नि.मं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि रामसाय आ० जगरनाथ का मृत्यु दिनांक 10/9/2024 को ग्राम कुरीडीह में हुई है, अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नही करा पाया है। आवेदक अपने पिता रामसाय आ जगरनाथ का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत कुरीडीह को आदेशित करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक..15/12/25 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 1/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
भैयाथान
जिला - सूरजपुर (छ०ग०)

धारावी में अदानी का मनमाना करोबार

मुंबई , धारावी बचाव आंदोलन के प्रमुख साथियों और धारावी शिवसेना के शाखा प्रमुख और पदाधिकारियों की एक बैठक युवासेना प्रमुख विधायक आदित्या ठाकरे के साथ हुई, इस बैठक में खासदार अनिल देसाई, आमदार महेश सावंत भी थे.सभी ने अदानी के मनमाना करोबार की निंदा की तथा सरकारी यंत्रणा को अदानी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, मीटिंग में धारावी और ऊहछ से संबंधी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई. अदानी की कम्पनी ठटउछछ के मनमाने करना और सरकारी तंत्र का अदानी के प्रति समर्पण पर विचार विमर्श किया गया. अदानी की कम्पनी नोटेड क्रिमिनल को अपने बाउंसर में शामिल किया है जो सर्वे कराने का काम या जहाँ कंही भी कंस्ट्रक्शन का काम या घर खाली कराने के काम या धमकाने का काम में इसको ईस्तेमाल कर रहा है. इसपर पर भी चर्चा हुआ की अदानी के अवैध सर्वे को धारावीकर विरोध कर रहे हैं,जो कागज नहीं दे रहा है उसे अदानी की कम्पनी ठटउछछ ले लोग धमका रहे हैं,जनता से कहा जा रहा है कि पांच कागज नहीं दोगे तो घर नहीं मिलेगा. गली मुहल्ले में दलाल और बाउंसर को लेकर घूम घूम कर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, फोन पर भी लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, धारावी के विभिन्न जगह अदानी की ऑफिस है जिस में बुला बुला कर डराया जा रहा है, कागज पर हस्ताक्षर लिया जा रहा है. ठटउछछ के कर्मचारी बाउंसर के साथ घर में जबरदस्ती घुस कर कागज मांग रहे हैं , नहीं देने पर मार पीट करने लगते हैं हाल में ही कमला नगर जैस्मीन मिल रोड की घटना है एक 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक को मारा, जिसका कंप्लेंट धारावी बचाव आंदोलन के नेताओं से शाहूनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है. धारावी बचाओ आंदोलन के नेता कामरेड नसीरुल हक ने बताया कि धारावी के मेघवाड़ी में 450 रहवासियों में सिर्फ 60 लोगों को पात्र किया है, बांकी सबी अपात्र है. जो पात्र हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को 33 और 38 नियम के तहत नोटिस दिया है की 3 महीना का भाड़ा लेकर घर खाली कर दो, नहीं तो पुलिस या मिलिट्री लगा कर घर खाली करा देंगे. ऐसा तानाशाही फरमान रफअ ने जारी किया है. यही हाल पटेल नगर, आजाद नगर और तिलक नगर का है जहाँ 85 प्रतिशत लोगों को अपात्र कर दिया गया है. 29 नवंबर को रात में मेघवाड़ी हजारों रहवासियों की एक बैठक हुई जिसे सांसद अनिल देसाई ने संबोधित किया और रहवासियों को घर खाली नहीं करने के लिए कहा. धारावी कोलीवाड़ा पर भी चर्चा हुई , जब धारावी नहीं बसा था, तभी से कोलीबड़ा कोई 300 साल पुराना कोली समाज का गांव है. आज भी जहाँ भी कोलीवाड़ा उन्हें गांवठी स्टेटस प्राप्त है, उसी आधार पर धारावी कोलीवाड़ा धारावी के पुनर्वास अदानी प्रोजेक्ट से बाहर था जिसका विकास म्हाडा या ठटउछछकरने वाला था, परंतु यह सरकारी कम्पनियों ने यह जमीन एक तरफा फैसला लेते हुए अदानी को हस्तांतरित कर दिया है, और जबरदस्ती वहां ठटउछछ वाले ने सर्वे करना शुरू कर दिया है, जिसका विरोध वहां के कोली समाज कर रहे हैं. कामरेड ने बताया कि इसी तरह माहिम फाटक 13 कंपाउंड के व्यवसायियों और रहवासियों पर दबाब बनाया जा रहा है की सर्वे करा लो, जब की वहां के लोगों की अपनी मांग है जो अदानी को दिया है उस पर उनके साथ कोई चर्चा नहीं कर रहा है. कुम्हारवाड़ा जो ब्रिटिश काल में ही बसा है और उनका उस जमीन का एग्रीमेंट भी ब्रिटिश सरकार के साथ है, उन्हें एक स्वतंत्र पोर्टर बिजनेस हब की मान्यता है. उसे भी अदानी को दे दिया और अदानी कंपनी कुम्हारवाड़ा के लोगों को मुलुंड भेजना चाह रही है, वहां के लोगों ने सर्वे कराने से मना कर दिया और अपनी मांग अदानी के पास रखा है धारावी राजीव गांधीनगर ट्रांजिट कैंप वाले ने कागज देने से मना कर दिया और उनकी मांग है की हम लोगों को स्लम से निकाल कर चाल घोषित करो और उसके आधार पर पुनर्वास करो. धारावी के सभी झोपड़ों और चाल को पात्र घोषित का ऋफ निकाले सरकार से यह पहली मांग है. युवा सेना प्रमुख आदित्या ठाकरे ने कहा की जिस पद्दति से धारावी को अदानी को दिया वह बिल्कुल मैच फिक्सिंग था

अंतरिक्ष में नई ऊंचाई छूने के लिए निरंतर अग्रसर इसरो

सुदृढ़ संचार व्यवस्था हो या सामरिक सुरक्षा का मामला, कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी की बात हो या प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना हो, इन सबके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में नित नई ऊंचाई छूना जरूरी है। इस दिशा में इसरो निरंतर अग्रसर है। यही नहीं विश्व की स्पेस सुपर पावर बनने के लिए भी इसरो के पास कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग्स हैं। इन सभी पर एक विस्तृत नजर।

कवर स्टोरी

संजय श्रीवास्तव

इसरो द्वारा तीन साल के भीतर अंतरिक्षयान निर्माण की तीन गुनी क्षमता का लक्ष्य निर्धारण, भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा का पूर्वाभास है। यदि यह हासिल हो जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी भी न सिर्फ नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के समानांतर खड़ी होगी बल्कि विश्व अंतरिक्ष बाजार में भी वह बहुत बड़ी खिलाड़ी बन जाएगी।

देश की प्रगति के लिए जरूरी: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का अगले तीन वर्षों में अपने अंतरिक्षयान निर्माण क्षमता को तिगुना करने का फैसला, देश की बदलती सामरिक, वैज्ञानिक और आर्थिक प्राथमिकताओं के पूर्वाभास सरीखा है। इसरो चाहता है कि खुद को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सके, ताकि वो निजी कंपनियों की तेज भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा के बीच अविलंब आगे आ सके। उसकी यह पहल, देश को विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों की श्रेणी में ऊपरी स्थान दिलाने की दिशा में एक रणनीतिक विस्तार है।

अंतरिक्ष यान निर्माण क्षमता को बढ़ाना कई वजहों से जरूरी है। 5जी से बढ़कर 6जी की ओर बढ़ना है, तो सैकड़ों छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना ही होगा। पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी उपग्रहों की मांग भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़ेगी।

वैश्विक शक्ति बनने की है सामर्थ्य: वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में उपग्रहों और उनकी सेवाओं की मांग अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है। संचार, अर्थ ऑब्जर्वेशन, रक्षा, निगरानी, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में उपग्रहों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होने के चलते आने वाले दशक में हजारों नए उपग्रह लॉन्च होने की उम्मीद है।

भारत के पास सस्ता, तेज, कुशल और विश्वसनीय अंतरिक्ष अभियान संचालन की बेहतर क्षमता है, इसको पूरी दुनिया जान और मान रही है। तमाम देश इसके लिए भारत की ओर आकर्षित भी हैं। लेकिन अंतरिक्ष यान निर्माण-क्षमता के सीमित होने के कारण देश बेहतरीन कौशल होने के बावजूद इस तेजी से बढ़ती वैश्विक मांग का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा। इसरो अभी सालाना औसतन 6 से 7 अंतरिक्षयान बनाता है। तीन साल बाद क्षमता तीन गुना होने का मतलब है कि वह 18 से 21 अंतरिक्षयान प्रति वर्ष तैयार कर सकेगा। फिर उसके पास अन्य देशों के उपग्रहों के लांच के लिए न सिर्फ पर्याप्त यान होंगे बल्कि उन्हें लांच के लिए विंडो भी। कम समय अंतराल पर होने और निर्माण तथा लांच सुविधाएं सीमितता के चलते इसरो के कई प्रक्षेपण कार्यक्रम आपस में ओवरलैप करते हैं। इसरो द्वारा उत्पादन वृद्धि के साथ सैटेलाइट इंटीग्रेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाना इस ओवरलैप को कम करेगा। अंतरिक्षयानों की संख्या में वृद्धि भारत को वैश्विक प्रक्षेपण सेवाओं के बड़े बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धी बनाएगा, जहां आज अमेरिका की स्पेस-एक्स जैसी निजी कंपनियां लगभग एकछत्र राज कर रही हैं।

संभावनाएं-क्षमताएं हैं भरपूर: आज भारत, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में केवल 2 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, इसरो इसे 2030 तक 8 फीसद तक ले जाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। क्षमता विस्तार, निजी साझेदारी और नई तकनीकों का विकास इसे संभव बना सकता है। बेशक इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी दर्ज होगी तथा संबंधित क्षेत्र में साख भी बढ़ेगी। असल में इसरो की रणनीति महज अपने अंतरिक्ष यानों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इस दौर में जब देश में कई स्पेस स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं, इसरों की प्लानिंग है कि अंतरिक्षयान निर्माण में तमाम बड़ी निजी कंपनियों जैसे लार्सन एंड टुब्रो, गोदरेज, एचएएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, स्काईरूट, अग्निकुल, ध्रुव स्पेस तथा अन्य छोटे स्टार्टअप्स को भी वह इस काम में बड़े पैमाने पर साझेदार बनाए ताकि इससे भारत में 'एयरोस्पेस मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्री' का विकास तीव्र हो। वह अमेरिका में नासा और स्पेस-एक्स जैसे सरकारी एजेंसी और निजी कंपनी के आपसी सहयोग जैसे मॉडल को भारतीय परिस्थितियों में संभव बनाना चाहती है। इससे देश, संबंधित कंपनियों और आखिरकार इसरो को लाभ पहुंचेगा।

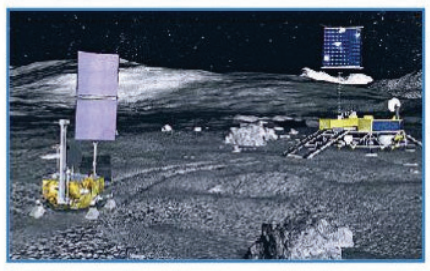

निजी क्षेत्रों को कर रहा प्रोत्साहित: जल्द ही भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी उद्योग-निर्मित पीएसएलवी इसी परिवर्तन की ज्वलंत निशानी बनेगा। इसरो खूब जानता है कि निजी क्षेत्र जितना बड़ा होगा, उसको उतनी ही सुविधा होगी। वह उन पर बहुत से तकनीकी और निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी देकर अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा प्रक्षेपण कार्यक्रमों एवं अनुसंधान मिशनों पर केंद्रित कर पाएगा। इसरो को निजी-सरकारी कंपनियों के सहयोग से तीन गुनी यान निर्माण क्षमता हासिल हो गई, तो उसका परोक्ष प्रभाव यह भी होगा कि इसरो के वैज्ञानिक मिशन तेजी से पूरे होंगे, वाणिज्यिक लॉन्च बढ़ेंगे। ऐसे में भारत वैश्विक उपग्रह-निर्माण और प्रक्षेपण बाजार में बेहद कमाऊ और प्रभावी खिलाड़ी बन सकेगा। इनके अलावा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और ज्यादा बढ़ेगी, तो विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होती जाएगी। बड़ी बात यह भी कि पांच मॉड्यूल वाला देश का अंतरिक्ष स्टेशन समय पर स्थापित करने की संभावना भी इससे मजबूत होगी।

कई स्तरों पर करनी होगी पहल: इसरो के सभी प्रोजेक्ट्स समय से पूरे हों, इस लिए भी इसरो को अपनी यान निर्माण क्षमता को तीन गुना बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। चंद्रयान-4 भारत के लिए अमेरिका के अपोलो कार्यक्रम की तरह विशिष्ट होगा। यह चंद्रमा से नमूने वापस लाकर भारत को उस सैंपल रिटर्न टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाएगा, जो संसार के महज तीन देशों के पास है। इसी तरह जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के साथ लूपेक्स मिशन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की मौजूदगी तलाश उसकी उपयोगिता समझने का अवसर देगा। यह भविष्य के मानव मिशनों के लिए ईंधन और पानी का स्रोत समझाएगा। भारत अपने अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को 2028 तक पूरा करते हुए 2035 तक पांच मॉड्यूल वाला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है। इस पूरे प्रकरण में सरकार की जो भूमिका हो सकती है, वह यह है कि उसके द्वारा अंतरिक्ष नीति और विनियमों को सरल बनाया जाए ताकि निजी निवेश, इसरो को लंबी अवधि की फंडिंग और स्टार्टअप ईकोसिस्टम को बढ़ावा मिले, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर नियमित निवेश एवं निजी भागीदारी को गति मिले, जिससे इसरो अधिक प्रक्षेपण केंद्र और ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित कर सके। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विस्तार पर भी सरकार को जोर देना होगा। फिलहाल इसरो का फैसला देश को वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में आर्थिक शक्ति बनाएगा, लाखों नौकरियों का सृजन, युवा वैज्ञानिकों के लिए अवसर पैदा करेगा। *

कई प्रोजेक्ट्स पर हो रहा काम

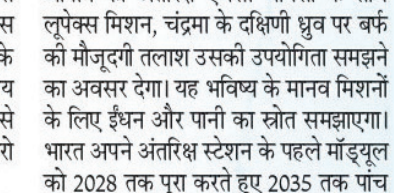

इसरो के लिए आने वाला दशक निर्णायक है। इस वर्ष और अगले वर्ष में इसरो के पास आधे दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शेष हैं और अगले कुछ वर्षों में संचालित होने वाले इसरो के पूर्व नियत कई प्रमुख अभियान तो बहुत जटिल और महत्वाकांक्षी हैं। गगनयान के कई मानव-रहित परीक्षण, मानव सहित गगनयान, 2028 में जाने वाला चंद्रयान-4, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिशन लूपेक्स, एसएसएलवी निर्माण तथा रि-यूजेबल लॉन्च व्हीकल का विकास, शुक्रयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, नई पीढ़ी के संचार उपग्रह जैसे कई महत्त्वाकांक्षी मिशन पर कार्य जारी है।

डिजिटल गेम्स वर्तमान है शानदार-उज्ज्वल है भविष्य

हाल के वर्षों में मनोरंजन के लिहाज से डिजिटल गेम्स का क्रेज जबर्दस्त तरीके से बढ़ा है, निरंतर इसमें इजाफा भी हो रहा है। खासतौर पर इसे लेकर नई पीढ़ी में बहुत दीवानगी देखी जाती है। इसकी क्या हैं वजहें और कैसा है भविष्य, जानिए।

टेक्नोलाइफ

लोकमित्र गौतम

आज के युग में मनोरंजन, शिक्षा और तकनीकी प्रयोग का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुके हैं-डिजिटल गेम्स। मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट और गेमिंग कंसोल के जरिए खेले जाने वाले ये खेल महज खेल नहीं हैं बल्कि आज की तारीख में अरबों रुपए का कारोबार भी है। नई पीढ़ी के बीच इन डिजिटल गेम्स का आकर्षण इतना अधिक है कि अब ये डिजिटल गेम्स एक पूरी संस्कृति का रूप ले चुके हैं।

क्या होते हैं डिजिटल गेम्स: डिजिटल गेम्स सही मायने में इलेक्ट्रॉनिक खेल होते हैं। इन्हें डिजिटल गेम इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये किसी डिजिटल डिवाइस के जरिए खेले जाते हैं। जैसे- कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट या वीडियो गेम कंसोल। डिजिटल गेम्स में ग्राफिक, ध्वनि और उपयोगकर्ता का सीधे-सीधे संपर्क या इंट्रैक्शन संभव है। यह इंट्रैक्शन या संपर्क दो तरीके से होता है। इसमें एक है वर्चुअल अनुभव। वास्तव में यह किसी अनुभव के आधार पर तैयार किए जाते हैं और यहीं इनकी भूमिका बदल जाती है। यह केवल शारीरिक सक्रियता या महज मनोरंजन का कारण नहीं होते बल्कि कभी-कभी सीखने, कभी रणनीति बनाने, कभी निर्णय क्षमता को परखने या उसे विकसित करने तथा कभी-कभी हीनभावना को दूर करने का तरीका भी होते हैं।

दीवानी है नई पीढ़ी: नई पीढ़ी में डिजिटल गेम्स को लेकर बहुत ज्यादा आकर्षण या कहें क्रेज है। विशेषकर जनरेशन जेड और अल्फा, डिजिटल दुनिया में जन्मी, पली-बढ़ी पीढ़ियां इन खेलों की दीवानी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका बचपन मोबाइल और इंटरनेट के साथ खेलते और इस्तेमाल करते हुए गुजरा। इसलिए डिजिटल गेम्स को ये मनोरंजन नहीं कहते बल्कि अपने व्यक्तित्व की पहचान, प्रतिस्पर्धा और आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम मानते हैं।

इसलिए बढ़ रहा इतना क्रेज: नई पीढ़ी में डिजिटल गेम्स का इतना क्रेज इसलिए है, क्योंकि यह वास्तविक अनुभव देता है। आज के डिजिटल गेम्स में एक साथ वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी और एआर यानी ऑग्मेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल होता है, जिसे खिलाड़ी इन्हें दूर से खेलता हुआ नहीं लगता बल्कि खुद को वह खेल के भीतर का हिस्सा समझता है और खेल के रोमांच को पल-पल महसूस करता है। दुनिया के किसी कोने से किसी दोस्त के साथ, किसी अजनबी के साथ, इन खेलों को खेला जा सकता है यानी आज की डिजिटल लाइफ के अनुकूल ये ऑनलाइन गेम की सुविधा प्रदान करते हैं और सबसे आकर्षक बात यह है कि डिजिटल गेम्स, एक रिवॉर्ड सिस्टम से भी जुड़ा होता है यानी प्वाइंट, लेवल और खरीदारी के लिए वाउचर जैसी सुविधाओं का मौजूद होना खिलाड़ियों को अलग ही दुनिया के रोमांच से जोड़ देते हैं। आज की तारीख में डिजिटल गेम्स महज खेलने की डिजिटल गतिविधि भर नहीं हैं बल्कि यह एक किस्म की सामाजिक प्रतिष्ठा बन चुके हैं। युवाओं में गेमिंग अब अपने आपमें एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोकप्रिय गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और फैंस भी मिलते हैं। इस तरह डिजिटल गेम्स मनोरंजन करने के साथ-साथ हमारे तनाव मुक्ति का भी जरिया हैं। इस कारण भी युवाओं में डिजिटल गेम्स को लेकर जबरदस्त क्रेज है।

ऐसे हुई डिजिटल गेम्स की शुरुआत: वर्ष 1962 की बात है, एमआईटी यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका में दो युवाओं ने मिलकर दुनिया का पहला डिजिटल गेम स्पेस वार बनाया। स्टीव रसेल और उनके दोस्त मार्टिन ग्रेट्ज ने पहले-पहल इस डिजिटल गेम्स की अवधारणा को 1961 में रखा था। लेकिन बाद के एक साल में उनके साथ उनके चार और दोस्त आ जुड़े, ये थे- वेन विटानन, पीटर सैमसन, डेन एडवर्ड्स और एलन कोटाक। इन सभी ने मिलकर दुनिया का पहला डिजिटल गेम्स स्पेस वार सीडीपी-1 कंप्यूटर पर बनाया। यहीं से आधुनिक वीडियो गेम उद्योग की शुरूआत हुई।

जहां तक भारत में डिजिटल गेमिंग की शुरुआत का सवाल है तो यह सन 1990 के दशक में आया, जब कंप्यूटर और इंटरनेट भी धीरे-धीरे आम लोगों तक पहुंचने लगे थे। भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल गेम 'भारतः द गेम' (1998) माना जाता है, जिसे सिनका गेम्स कंपनी ने विकसित किया था। हालांकि गेम बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ।

डिजिटल गेम्स का भविष्य: जहां तक डिजिटल गेम्स की दुनिया के भविष्य का सवाल है तो यह बेहद उज्ज्वल और तकनीकी रूप से बेहद रोमांचक है। साल 2025 में वैश्विक गेमिंग इंडस्ट्री बढ़कर 250 अरब अमेरिकी डॉलर की हो चुकी है और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा भारत के डिजिटल गेम्स प्रेमियों का भी है। क्योंकि साल 2024 के अंत तक भारत में सक्रिय गेम्स की संख्या बढ़कर 40 करोड़ हो चुकी है। शायद यह डिजिटल गेमिंग का ही विस्तार है कि आज ई-स्पोर्ट्स की दुनिया बड़े पैमाने पर उभरी है और लाखों लोग इसे अपना करियर बनाकर अपना भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित कर रहे हैं। *

कविता

पुरुषोत्तम व्यास

गिरना भी अच्छा होता

कभी-कभी गिरना भी अच्छा होता,
गिरने से संभलना सीखते
फिर चलना सीखते।
समझ में आता है
अति हर चीज की
अच्छी होती नहीं,
बात-बात पर अहंकारी,
और ज्यादा ज्ञानी
समझने से बच जाते।
बात यह भी जरूरी है कि
गिरने को किस रूप में देखते हो,
विचलित होते हो या
नए साहस से आगे बढ़ते हो
गिरने से दिमाग भी
ठिकाने रहता
अपने और पराए पर
पर्दा उठ जाता।
अगर गिरे तो फिर
नए रूप लेकर उठो
नए विचार लेकर उठो
बेफिक्र होकर जीना सीखो
इसलिए कभी-कभी
गिरना भी अच्छा होता है।

व्यंग्यात्मक संस्मरण

डॉ. मुकेश असीमित

टिकट विंडो की लाइन

रेलवे स्टेशन की टिकट विंडो आजकल किसी आध्यात्मिक तप जैसी लगती है। अमृत योजना का थोड़ा-बहुत बजट खर्च कर चार खिड़कियां बना दी गई हैं, पर चारों के सामने उतनी ही लंबी लाइनें, मानो चार अलग-अलग धर्मपंथ हों और भक्त सभी जगह समान संख्या में हों।

मैं बड़ी होशियारी से सबसे छोटी लाइन में लगा, और जैसे ही लगा किस्मत मेरी गर्दन पकड़कर मुझ पर हंस रही हो जैसे। मेरी लाइन कछुए की चाल से और बाजू वाली लाइन खरगोश की गति से फुर्र-फुर्र बढ़ती जा रही थी।

खिड़की पर एक बुजुर्ग बाबू थे, शायद रिटायरमेंट के ठीक पहले के अंतिम वर्ष में। चश्मा उतारते, लगाते, की-बोर्ड को किसी वेद-पाठ की तरह एक-एक अक्षर छूते। स्क्रीन पर अक्षर प्रकट होता तो उनके चेहरे की झुर्रियां भी खिल उठतीं, मानो तकनीकी उन्नयन का चमत्कार उन्हें रोज नई जवानी दे रहा हो। रेलवे ने शायद फैसला कर रखा है कि यह महाशय अपना अंतिम प्रण और अंतिम प्रणय दोनों इसी खिड़की पर छोड़ेंगे।

इतने में एक दुबला-पतला अधेड़ मेरी कोहनी पसलियों में गड़ाता हुआ फुसफुसाया, 'कौनसी ट्रेन चाहिए साहब? बोलो तो जुगाड़ कर दूं, अंदर तक पहुंच है। बस सौ का एक नोट एक्स्ट्रा।'

मैंने विनम्रता से मना कर दिया। विनम्रता पर उसने जर्दे-भीगे होंठों से मोबाइल और मुझे संयुक्त रूप से एक गाली दी और फुर्र हो गया। उसकी प्रतिक्रिया खीझ से उत्पन्न हुई, जैसे कोई एक डील होते-होते रह गई हो।

मोबाइल ही आजकल इन लंबी लाइनों का आधुनिक तपो-साधन है, सभी यात्री उसमें गुम। मैं भी व्हाट्सएप की दुनिया में तल्लीन था, तभी आगे शोर हुआ। एक यात्री जिसकी ट्रेन छूटने वाली थी, लाइन तोड़कर हथेली खिड़की के नैनो साइज के छेद में घुसा चुका था कि दूसरा यात्री अपना हाथ निकाल ही नहीं पा रहा था। अब विवाद यह नहीं कि किसकी बारी, बल्कि यह कि सबसे पहले हाथ कौन निकाले!

बाबू ने सीटी बजाई। दो पुलिसकर्मी अपनी तोंदें, बाल्टी की तरह लटकाते हुए आए। लाठी को हवा में घुमाते हुए स्थानीय भाषा में अपशब्दों का ऐसा समन्वित गान किया कि लाइन तुरंत सीधी हो गई। दोनों यात्रियों के हाथ बड़ी मुश्किल से निकाले गए। इस खींचतान में एक की हस्त-धारित भारतीय मुद्रा फट गईं और उसके मुंह से निकली गालियां व्यवस्था की संपूर्ण संस्थाओं को समर्पित थीं, रेलवे, सरकार, मंत्री से लेकर कुली तक कोई नहीं छूटा।

मैं फिर मोबाइल में चला गया। नया वर्ष आने में महीना है लेकिन कंपनियां जैसे चाहती हैं कि इस बार मैं चार नए कपड़ों, दो नई चॉकलेटों और पांच नए कूपनों से लैस रहूं। ऑफर ऐसे कि लगता है हर कंपनी ने मेरे लिए ही सुकुमारी ब्रांड की मॉडल को विज्ञापन में खड़ा किया है। एक बार जल्दबाजी में मैंने सुकुमारी के मोहपाश में बंधे सब्सक्रिप्शन डाल दिया था, तभी से वह मेरे जीवन की स्थाई सदस्य बन चुकी है।

मोबाइल भी क्या करे। कंपनियां चाहती हैं कि आप दिन-रात उसी से चिपके रहो। कभी धमाका सेल, कभी फ्लैश सेल, कभी लास्ट स्टॉक, हड़प लो!

नई पीढ़ी को ये सेल-ऑफर ऐसे जकड़ती है कि किसी उल्टे-सीधे काम में ऊर्जा लगे, उससे अच्छा है कि स्क्रीन पर अंगूठा फिसलाते रहो। गेम्स, जुआ, सट्टा, लॉटरी सब आपके दरवाजे पर नहीं, आपकी जेब में बैठा है।

इधर मेरा मोबाइल भी मेरा पूरा जीवन समझता है- कब रिचार्ज खत्म होगा? कब बीमा एक्सपायर होगा? कब कार की सर्विसिंग करानी है?

कब पुरानी कार बेचे चार साल हो गए? यह सब याद दिला रहा है।

सच कहूं तो मोबाइल ने आदमी को अकेला किया, या अकेलापन आदमी को मोबाइल तक ले गया, ये तफरीक अब मैं भी नहीं कर पाता।

मोबाइल पर आध्यात्मिक गुरुओं के संदेश, प्रेरक कथन और भविष्यवाणियां भी तड़ातड़ आ रहे हैं। सुबह-सुबह इतनी 'ज्ञान-वर्षा' कि दिमाग की हार्ड डिस्क फुल होकर ओवरहीट हो जाए। पर सही कहूं, रेलवे की लाइनें और मोबाइल दोनों ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की लाइफलाइन हैं। एक में लगकर देश चलता है और दूसरे में खोकर आदमी। इतने में मेरी लाइन भी दो-चार इंच आगे बढ़ गई।

शायद मेरे नंबर का भी समय आ रहा था और मोबाइल पर एक नया मैसेज भी। *

लघुकथा / सतीश उपाध्याय

दरवाजा

'ममी, दादाजी की वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बार-बार हमारे कमरे में आ जाते हैं।' परेश ने अपनी मां से दादाजी की शिकायत की। सामने कुर्सी पर बैठे दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, वह तुरंत बोले, 'नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुमको मैंने तीन घंटे से नहीं देखा था, इसलिए ऐसे ही तुम्हें देखने तुम्हारे कमरे में चला आया था।' परेश की मम्मी बेटे का पक्ष लेते हुए बोलीं, 'बाबूजी, थोड़ा बुद्धि से काम लिया करिए। स्कूल से कितना होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट पूरा करना होता है। अगर वह आपसे बात करेगा तो उसका होमवर्क कैसे पूरा हो पाएगा?' दादाजी आहिस्ता से बोले, 'बेटा बात सही है, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा।' अगला दिन छुट्टी का था। परेश सारा दिन अपने लैपटॉप और मोबाइल में ही बिजी था। दादाजी के भीतर अपने पोते के प्रति प्यार उमड़ा तो वह अपने आपको रोक नहीं पाए। परेश के कमरे में चले गए। परेश के बेड पर स्कूल की कॉपी-किताबें बिखरी हुई थीं। वह मोबाइल में बिजी था। उसने दादाजी की आहट सुनी, लेकिन वह दादाजी की उपेक्षा करते हुए अपने मोबाइल में ही लगा रहा। दादाजी ने पूछा, 'क्या कर रहे हो बेटा?' परेश रूखे स्वर में बोला, 'दादाजी देख नहीं रहे हैं, मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर रहा हूं। आप डिस्टर्ब मत करिए।' 'ठीक है बेटा, कितना समय लगेगा, इसे पूरा करने में?' दादाजी ने बड़े प्यार से पूछा। 'दादाजी मैं अभी कैसे बता दूं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज।' परेश ने तेज स्वर में बोला। 'ठीक है बेटा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।' यह कहकर दादाजी ने कमरे से बाहर निकलते समय पलटकर देखा, परेश अपने मोबाइल में लगा दिखा। दादाजी के कमरे से निकलते ही परेश ने अपने कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद कर दिया। दादाजी कुछ देर दरवाजे के पास भाव शून्य खड़े रहे। उनकी आंखों में एक नमी उतर आई थी। *

पुस्तक: छवि से अलग (संस्मरण), **लेखक:** विनोद दास, **मूल्य:** 295 रुपए, **प्रकाशक:** सेतु प्रकाशन, नोएडा

पुस्तक चर्चा / विज्ञान भूषण

छवि से अलग

हाल में ही वरिष्ठ साहित्यकार विनोद दास के संस्मरणों की पुस्तक 'छवि से अलग' छपकर आई है। इसमें चौदह नामचीन साहित्यकारों के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा संस्मरण भी संकलित है। इन संस्मरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें सम्मिलित हस्तियों की कई अनावृत्त रही छवियां उजागर होती हैं। ये छवियां उनके साहित्यिक ही नहीं व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। लेखक ने निरपेक्ष भाव से इनकी खूबियों और खामियों को सामने रखा है। इसके साथ ही साथ कई संस्मरणों में लेखक, समानांतर रूप से उस देश, काल और परिस्थितियों का भी वर्णन करते चलते हैं, जब इन अनुभूतियों को वे अर्जित कर रहे थे। निर्मल वर्मा, नामवर सिंह, श्रीलाल शुक्ला, कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, अखिलेश, शानी और मुद्राराक्षस जैसे कई साहित्यकारों के बारे में यह किताब बहुत कुछ अनसुना बताती है। *

तुंहर टोकन ऐप धान खरीदी व्यवस्था को बना रहा भरोसेमंद और पारदर्शी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के मार्गदर्शन में जिले में धान खरीदी तिहार सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन की सतत निगरानी और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के चलते उपार्जन केंद्रों में तुलाई, बारदाना, भुगतान तथा स्टाफ की उपलब्धता संतोषजनक है, जिससे किसानों को बिना किसी परेशानी के धान विक्रय करने में सहूलियत मिल रही है। समर्थन मूल्य 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल मिलने से किसानों में उत्साह का वातावरण है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 1,83,937.6 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है।

निर्धारित तिथि एवं समय पर टोकन के आधार पर किसान उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान बेच रहे हैं। मोबाइल आधारित तुंहर टोकन ऐप किसानों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो रहा है। इस प्रणाली के लागू होने से केंद्रों में लंबी कतारों की समस्या समाप्त हो गई है। अब किसान अपने तय समय पर पहुंचकर आसानी से धान विक्रय कर रहे हैं। अब तक कुल 3,515 टोकन जारी किए गए हैं, जिनमें से समिति द्वारा जारी टोकन संख्या 1,643, ऐप के माध्यम से जारी टोकन संख्या 1,872 हैं।

समिति टोकन के आधार पर 77,726.4 क्विंटल धान तथा ऐप टोकन से 1,06,211.2 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। उल्लेखनीय है कि तुंहर टोकन ऐप खरीदी व्यवस्था को पूर्व की अपेक्षा अधिक तेज, भरोसेमंद और पारदर्शी बना रहा है।

पेड़ से टकराई श्रद्धालुओं की बुलेरो, एक की मौत, 4 गंभीर

म.प्र. के कुम्हिया से कुदरगढ़ दर्शन के लिए आए थे 8 श्रद्धालु, वापस लौटते समय हुआ हादसा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिहरपुर। मां कुदरगढ़ धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं का सफर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे में तब्दील हो गया। ओड़गी थाना क्षेत्र के बांक के पास श्रद्धालुओं से भरी बुलेरो वाहन क्र यूपी 61 ए ए 6191 अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े महुआ पेड़ से जा टकराई, टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे यात्रियों की चीख-पुकार मच गई।

इस हादसे में मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के कुम्हिया निवासी सतीश ठाकुर की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में कुल 8 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि अन्य तीन को हल्की चोटें आई हैं। मृतक और सभी घायल एक ही गांव के बताए जा रहे हैं, जो रविवार सुबह कुदरगढ़ धाम में दर्शन करने पहुंचे थे और शाम को वापस लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक घटना हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को ओड़गी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां गंभीर घायलों का उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों में कई के सिर, पैर और छाती में गंभीर चोटें हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए रेफर करने की तैयारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बुलेरो वाहन तेज रफ्तार में था, जिससे चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और वाहन सीधे पेड़ से जा टकराई। जिस स्थान पर हादसा हुआ है, वह पहले भी दुर्घटना संभावित क्षेत्र माना जाता रहा है, जहां शाम के समय दृश्यता कम होने के कारण हादसों की आशंका बढ़ जाती है।

पुलिस जांच में जुटी घटना की सूचना पर ओड़गी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मर्ग कायम कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ग्रामीणों से भी हादसे के संबंध में बयान ले रही है। सतीश ठाकुर की मौत की खबर कुम्हिया गांव पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सुरक्षा प्रबंधन और चेतावनी संकेतक लगाने की मांग की है।

जिले में कल होगा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन

मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी मंत्री लक्ष्मी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 3 दिसम्बर को यहां रंगमंच में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना है। कलेक्टर एस.जयवर्धन द्वारा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटले को नोडल अधिकारी एवं श्रीमती बेनदिक्ता तिर्की, उप संचालक समाज कल्याण तथा विक्रम बहादुर, उप संचालक पंचायत जिला पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन कर दिया गया है और सभी को कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप तैयारीयां सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आयोजित उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े होंगी।

वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य व जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल के द्वारा की जायेगी। कार्यक्रम में छ.ग. राज्य वन विकास निगम अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, सरगुजा सांसद चिन्तामणि महाराज, प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मराबी, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते एवं जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चन्द्रमणी पैकरा, जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्वाति सिंह, जिला पंचायत एवं जनपद सदस्य, पार्षद जनप्रतिनिधि जिले के गणमान्य नागरिक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

आवारा कुत्तों के प्रबंधन एवं जन सुरक्षा पर जोर, निदान 1100 हेल्पलाइन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने संस्थागत एवं शहरी क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए विभिन्न विभागों को जन सुरक्षा एवं आवारा कुत्तों के प्रभावी प्रबंधन के लिए निर्देश जारी

किए हैं। इसी क्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संचालित जन शिकायत निवारण प्रणाली-हेल्पलाइन नंबर निदान 1100 जारी किया गया है ताकि नागरिक आवारा कुत्तों तथा अन्य जनसमस्याओं से संबंधित शिकायतें बिना किसी विलंब के दर्ज करा त्वरित निराकरण प्राप्त कर सकें।

प्रदूषण मुक्त हरित पर्यावरण पर महाविद्यालय में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। प्रदूषण मुक्त हरित पर्यावरण के महत्व पर जिले के रामानुजनगर महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम कलेक्टर एस. जयवर्धन के आदेशा तथा कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदुषण मुक्त हरित पर्यावरण के महत्व पर जागरूकता एवं छात्र छात्राओं को महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा से बचने के लिए सशक्त बनने और जागरूक होने हेतु प्रेरित किया गया। इसके साथ में घरेलू हिंसा, अधिनियम, टोनही प्रताड़ना अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिंक उत्पीड़न अधिनियम, सखी वन स्टॉप सेंटर एवं टोल फ्री नंबर 1098, 181, 112 की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में श्रीमती इंद्र कुमारी तिवारी, श्रीमती विनीता सिन्हा, श्रीमती शारदा सिंह एवं प्रचार्य तथा छात्र व छत्राएं उपस्थित रहे।

सिकंदराबाद अंतर सर्विसेज वालीबॉल चैंपियनशिप में निर्णायक होंगे अंतर्राष्ट्रीय रेफरी गौस बेग

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सिकंदराबाद में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित 75 वीं अंतर सर्विसेज वालीबॉल चैंपियनशिप 1 से 5 दिसंबर तक किया जा रहा है। जिसमें सर्विसेज के अंतर्गत इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स एवं इंडियन आर्मी के टीमें भाग ले रही है। यह चैंपियनशिप भारत के सर्वश्रेष्ठ चैंपियनशिप में से एक है जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। वालीबॉल फेडरेशन ऑफ़ इंडिया द्वारा इस चैंपियनशिप के सफल संचालन हेतु भारत से दो रेफरी को नियुक्त किया गया है जिसमें सरगुजा संभाग के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी सूरजपुर जिले के मोहम्मद गौस बेग का चयन किया गया है। जो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदित हो कि गौस बेग को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के

साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में ऑफशियटिंग करने का खासा अनुभव प्राप्त है। इस चैंपियनशिप में इंडियन सर्विसेज टीम का गठन किया जाना है। सर्विसेज टीम इस वर्ष नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल एवं पिछले वर्षों में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी गोल्ड एवं सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 2024 में वर्ल्ड मिलिट्री वालीबॉल चैंपियनशिप ईरान में भारत की सर्विसेज टीम ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया था ।

भारत की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में निर्णायक हेतु अंतर्राष्ट्रीय रेफरी गौस बेग के चयन होने पर छत्तीसगढ़ वालीबाल संघ के प्रमुख मोहम्मद अकरम खान, सचिव हेम प्रकाश नायक छत्तीसगढ़ रेफरीज बोर्ड के चेयरमैन विनोद नायर एवं सूरजपुर वालीबाल संघ के अध्यक्ष अजय गोयल व सचिव राम श्रृंगार यादव ने शुभकामनाएं दी है।

पैरा जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण, किसानों को गौठानों में पैरा दान हेतु प्रोत्साहित करने निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में खरीफ सीजन की कटाई के दौरान बड़ी संख्या में कम्बाइन हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर से कटाई उपरांत खेतों में पैरा फैल जाता है जिसे किसान प्राय: समेटते नहीं हैं और खेत में ही जला देते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है तथा पशुओं के लिए चारे की कमी भी पैदा हो जाती है। प्रशासन ने बताया कि खेतों में फैले पैरा को आसानी से एकत्र किया जा सकता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस उद्देश्य से ग्राम पंचायतों में निर्मित गौठानों में सालभर पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो सके, इसके लिए गौठान प्रबंधन समिति एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गांव के किसानों को पैरा दान करने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अग्रसेन चौक पर किया प्रदर्शन, फूंका पुतला

नेशनल हेराल्ड मामले में मोदी सरकार पर तानाशाही का लगाया आरोप

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मोदी सरकार के द्वारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने के मामले में धमकी की राजनीति और तानाशाही रवैये के मामले में कांग्रेस के प्रदेशव्यापी आह्वान तहत सोमवार को यहां अग्रसेन चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि देश में अर्थव्यवस्था की बर्बादी, फैलती नफरत, बेरोजगारी, फेल विदेश नीति के साथ अमेरिका और चीन की धमकी से देश का ध्यान भटकाने के लिए केन्द्र सरकार नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को उछाल रही है और कांग्रेस व गांधी परिवार के खिलाफ लगातार तानाशाही मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राष्ट्र व प्रदेश स्तर पर इसका विरोध सड़क में

उतरकर किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष शशि सिंह के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय डोसी की अगुवाई में अग्रसेन चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस को चकमा देकर पुतला दहन किया और पुलिसकर्मियों के साथ कांग्रेसियों की झुमाझटकी भी हुई। इस दौरान जीएस मिश्रा, विमलेश दत्त तिवारी, सुनील अग्रवाल, दीप्ती स्वाई, विनय मिश्रा, बिहारी कुलदीप, प्रवेश गोयल, प्रदीप साहू, नरेन्द्र यादव, विक्की समद्दार, परमेश्वर राजवाड़े, दिलीप सोनी, सकील हुसैन, अजय सोनवानी, देवेश राजवाड़े, इमरान इराकी, पारस राजवाड़े, कौनेन अंसारी, लालचंद देवांगन, संजय सोनी, कुंदन विश्वकर्मा, भोला शर्मा, मो. अजहर, जबारूल खान, गिरधारी साहू, सुनील सारथी, आशीष सिंह, समीर, विनोद सिंह, शांतू डोसी, दीपक साहू, शक्ति ठाकुर, रामनारायण, हेमंत साहू, बालेन्द्र सिंह, जमील सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, एनएसयूआई तथा अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

धान खरीदी व्यवस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण करने कलेक्टर पहुंचे महाराजगंज एवं चांदो

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। धान उपार्जन व्यवस्था को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने आज महाराजगंज एवं चांदो धान उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्र में चालू खरीदी व्यवस्था, किसानों के लिए की गई तैयारियों तथा व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया।

कलेक्टर ने सर्वप्रथम केन्द्र में आने वाले धान की नमी की जांच की प्रक्रिया का जायजा लेते हुए धान का नमी परीक्षण पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बारदाने की उपलब्धता की भी जानकारी ली तथा कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध रखने के निर्देश दिए, ताकि खरीदी कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री कटारा ने टोकन वितरण प्रणाली एवं ऑनलाइन एंट्री की शुद्धता की भी जांच की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन डेटा समय पर और सटीक दर्ज किया जाए, जिससे किसी भी किसान को खरीदी प्रक्रिया या भुगतान में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि किसी भी दिन अव्यवस्था की स्थिति न बने इसके लिए पहले से सभी आवश्यक प्रबंध मजबूत रखें। बदलते मौसम को देखते हुए कलेक्टर श्री कटारा ने धान उपार्जन केन्द्र में धान को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। उन्होंने खरीदी व्यवस्था के दौरान मौसम की जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के

साथ पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम रखने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा एवं पारदर्शी खरीदी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर ने केंद्र परिसर में धान तौल व्यवस्था, सुरक्षा, अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर सभी संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए।

करचा बैरियर का किया निरीक्षण

कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा ने करचा बैरियर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैरियर से होकर गुजरने वाले वाहनों की निगरानी हेतु लगाए गए सीसीटीवी कैमरों तथा पंजी रजिस्टर का अवलोकन किया। कलेक्टर ने वाहनों के आवागमन की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करते हुए बैरियर परिसर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों से विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने अवैध धान की संभावित आवक को ध्यान में रखते हुए सभी वाहनों की कड़ाई से जांच करने के निर्देश दिए। श्री कटारा ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने के साथ ही अवैध परिवहन पर सख्त निगरानी आवश्यक है। उन्होंने प्रत्येक वाहन की अनिवार्य रूप से जांच करने तथा संदिग्ध वाहनों पर विशेष ध्यान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

समर्थन मूल्य से किसानों की मेहनत को मिल रहा उचित मूल्य

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। किसानों की महीनों की कठिन मेहनत अब उपार्जन केंद्रों में खुशियों के रूप में दिखाई दे रही है। खेत में बीज से लेकर बालियों के पकने तक लगभग चार से छः महिना की लगन और परिश्रम का प्रतिफल आज किसानों को उनके अनमोल मूल्य के रूप में मिल रहा है। राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में भी धान को प्रति क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 3100 रुपये पर खरीदा जा रहा है। इस सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था से किसान संतुष्ट हैं, जिसकी झलक उनके

मुस्कुराते चेहरों में साफ दिखाई देती है।

बलरामपुर जिले के ग्राम सेमली निवासी किसान श्री जयशंकर सिंह ने इस वर्ष अपनी मेहनत से 275 बोरी धान की उपज प्राप्त की है। उन्होंने बलरामपुर धान उपार्जन केंद्र में अपना धान बेचा। वे बताते हैं कि उनकी खेती में पत्नी तथा परिवार के सदस्यों का संयुक्त योगदान रहता है। धान खरीदी प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री जयशंकर ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर खरीदी, सुविधाजनक व्यवस्था और उचित मूल्य प्रदान किए जाने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि धान बेचने के बाद अब वे गेहूं की बुवाई की तैयारी में जुट गए हैं। धान विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग वे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा खेती को और उन्नत बनाने में करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार किसानों के कठिन परिश्रम का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। समर्थन मूल्य पर सुगम, पारदर्शी और सुविधाजनक धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों में आत्मसंतोष का संचार किया है। शासन के दूरदर्शी पहल के कारण श्री जयशंकर जैसे अनगिनत किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौटी है। कृषक श्री जयशंकर सिंह ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को आभार व्यक्त किया है।

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 9713108088
8719000259

कोरिया फ्रंटलाइन

कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह कर रहीं जिले का सघन दौरा

अवैध कारोबार और नशे के नेटवर्क पर कसने लगी लगाम

छ.ग.फ्रंटलान

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। जिले में हाल ही में पदस्थ हुई पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त तेवर अपना लिये हैं। उनके द्वारा जिले भर के सभी थानों, चौकियों और संवेदनशील क्षेत्रों का सघन और आकस्मिक निरीक्षण लगातार जारी है। अचानक किये जा रहे आकस्मिक निरीक्षण से कानून व्यवस्था में सक्रिय ढीलापन समाप्त होने लगा है। निरीक्षण के दौरान एसपी सिंह ने थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और जांच अधिकारियों की मीटिंग लेकर साफ कहा की नशे का कारोबार जिले में किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अवैध शराब, गांजा, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन आधारित नशे तथा अन्य प्रतिबंधित पदार्थों के कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर तत्काल कार्यवाही की जाये। मुखबिर तंत्र को मजबूत किया जाये और संदिग्ध गतिविधियों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाये। पुलिस की गश्ती टीमों को सक्रिय करते हुए भीड़भाड़ वाले बाजार, स्कूल कॉलेज मार्ग, बस स्टैंड, हाईवे और ग्रामीण इलाकों में सघन जांच चलाई जाये। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि किसी भी थाना प्रभारी की लापरवाही या मिलीभगत पाये जाने पर कड़ी विभागीय कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगी। एसपी रत्ना सिंह के जिले में सक्रिय होते ही नशा कारोबारियों तथा अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में अफरातफरी का माहौल है। कई क्षेत्रों में पुलिस की अचानक दबिश से संदिग्ध व्यक्तियों का मूवमेंट कम हुआ है वहीं पुलिस बल में भी नई ऊर्जा और अनुशासन देखने को मिल रहा है। पुलिस अधीक्षक ने संकेत दिये हैं कि आगामी दिनों में जिलेभर में विशेष अभियान चलाया जायेगा जिसमें तलाशी अभियान, रात्रि गश्त बढ़ोतरी, हाइवे और बॉर्डर पॉइंट पर चेकिंग, कोचिंग सेंटर, स्कूल-कॉलेजों के आसपास सतर्कता, होटलों, लॉज और किराए के कमरों की जांच जैसी कार्यवाहियां शामिल रहेंगी। पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नशे से जुड़ी जानकारी, अवैध कारोबार या संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां दिखती हैं तो वह पुलिस को तुरंत सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जायेगी।

हाईकोर्ट के निर्देश पर चिरमिरी में आवारा और पालतू कुत्तों का विशेष एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद नगर पालिक निगम चिरमिरी द्वारा सोमवार को पूरे शहर में व्यापक एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए आवारा और पालतू दोनों प्रकार के कुत्तों का टीकाकरण किया गया।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सभी नगरीय निकायों को स्पष्ट निर्देश दिये थे कि वे कुत्तों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें। आवारा और पालतू दोनों ही वर्गों का नियमित टीकाकरण कराएँ। टीकाकरण और सर्वे का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें। शहर में कुत्तों का सर्वे और टैगिंग कराएँ। संक्रमण की आशंका या काटने की घटना पर तत्काल कार्यवाही करें। न्यायालय ने यह भी कहा था कि देरी या लापरवाही पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। इन्हीं दिशा निर्देशों के पालन में नगर पालिक निगम चिरमिरी की स्वास्थ्य टीम ने विभिन्न वार्डों, बस्तियों, बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर जाकर बड़ी संख्या में कुत्तों को एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाई। टीम ने पशुपालकों को जागरूक करते हुए बताया कि रेबीज़ एक घातक संक्रमण है जो पशु से मनुष्य में फैल सकता है। इसलिए समय पर टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। निगम प्रशासन ने शहर वासियों से अपील की है कि अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराएँ। समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करें। किसी भी कुत्ते में आक्रामकता, अत्यधिक लार, असामान्य व्यवहार, भय या असामान्य शांति जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत सूचना दें। नगर निगम ने बताया कि भविष्य में भी नियमित टीकाकरण शिविर, जागरूकता कार्यक्रम और कुत्तों के पंजीकरण की प्रक्रिया को और सख्ती से जारी रखा जायेगा। टीकाकरण ना कराने वाले पशुपालकों पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। निगम प्रशासन ने कहा कि शहर को रेबीज़ मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन और नागरिकों दोनों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से चिरमिरी नगर पालिका लगातार सक्रिय प्रयास कर रही है।

मृतक के परिजन को 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

एमसीबी। प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के अंतर्गत तहसील खड़गवां के ग्राम रतनपुर, निवासी ब्रम्हा प्रसाद की तालाब में डूबने से हुई मृत्यु के पश्चात उनके वारिस श्री कुंवर जी को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। यह सहायता राशि पीड़ित परिवार को आपदा की कठिन घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु शासन द्वारा प्रदत्त राहत उपायों के अंतर्गत दी गई है।

साइबर सेल मनेंद्रगढ़ ने 13 मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए

कुल कीमत लगभग 3.50 लाख रुपये, अभियान में आईफोन सहित कई महंगे फोन हुए ट्रेस

छ.ग.फ्रंटलाइन

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)। पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा दीपक कुमार झा के निर्देश और पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह के मार्गदर्शन में साइबर सेल मनेंद्रगढ़ द्वारा 1 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 तक गुम हुए मोबाइल फोनों की सतत खोज अभियान चलाया गया। इस दौरान साइबर सेल टीम ने कड़ी मेहनत और तकनीकी निगरानी के आधार पर कुल 13 मोबाइल हैंडसेट बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए। बरामद मोबाइल फोनों की कुल अनुमानित कीमत 3,50,000 रुपये बताई गई है। इनमें एक एप्पल आईफोन, तथा मोटोरोला और रियलमी कंपनी के अन्य स्मार्टफोन शामिल हैं।नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा और साइबर संबंधी अपराधों की रोकथाम के लिए यह कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पूरे अभियान में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले, तथा टीम के सदस्य प्रधान आरक्षक पुष्कल सिन्हा, आरक्षक भूपेंद्र यादव, राकेश तिवारी और जितेंद्र ठाकुर का सराहनीय योगदान रहा। टीम की तकनीकी दक्षता और निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप यह सफलता हासिल हुई।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को समर्पित जिला स्तरीय सम्मान कार्यक्रम कल

एमसीबी। जिले में दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने, उन्हें समान अवसर एवं अधिकार प्रदान करने तथा समाज के समक्ष उनके सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 03 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला स्तरीय दिव्यांगजन सम्मान समारोह का आयोजन जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के जनपद सभाकक्ष में 03 दिसम्बर 2025 को प्रात: 12 बजे से किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन समाज कल्याण विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के सहयोग से किया जा रहा है। सुचारु व्यवस्था हेतु विभागवार दायित्व निर्धारित किए गए हैं। उप संचालक समाज कल्याण विभाग को भोजन व्यवस्था, सम्मानित किए जाने हेतु सामग्री की व्यवस्था तथा बैनर आदि की तैयारी का दायित्व सौंपा गया है।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को दिव्यांगजनों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने तथा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

विश्व एड्स दिवस पर जागरुकता रथ के साथ रैली निकाली गई

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश में, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर कोरिया कलेक्ट्रेट परिसर से जागरुकता रथ रैली निकाली गई वापस कलेक्ट्रेट परिसर में रैली का समापन कर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया।

इस रैली में स्कूली बच्चे, राजवाड़े नर्सिंग इंस्टीट्यूट के नर्सिंग प्रशिक्षणार्थी एवं विभागीय अधिकारी - कर्मचारियों ने भाग लिया। शासकीय कृषि महाविद्यालय बैकुंठपुर में एड्स दिवस पर शपथ के साथ लोगों को नारा, माईकिंग, भाषण, मानव श्रृंखला विभिन्न गतिविधियां के द्वारा जागरुक किया गया। भाग लिये प्रतिभागियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत सिंह के द्वारा पुरस्कृत कर सर्टिफिकेट प्रदान किया गया जानकारी दी गई की विश्व एड्स दिवस पर रैली, नारे, भाषण आदि गतिविधियां सही मायने में तभी सफल होगा जब हम अपने आसपास के लोगों को एड्स के प्रति सजग जागरूक करेंगे, निगरानी करेंगे ऐसे क्षेत्रों का जहां एड्स संक्रमित पाए जाने की शंका हो। एड्स एक जान लेवा बीमारी है, अभी तक इसका इलाज उपलब्ध नहीं है, रोकथाम/बढ़ने को रोक सकते हैं। एआरटी सेंटर में कोई भी व्यक्ति एचआईवी की जांच एवं परामर्श ले सकता है। कोरिया जिले में तीन आई सी टी सी सेंटर है, तीनों आईसीटीसी सेंटर में लैब टेक्नीशियन, काउंसलर पदस्थ हैं। जिनके द्वारा क्षेत्र से आये व्यक्तियों की जांच एवं उपचार व्यवस्था की परामर्श दी जाती है। व्यक्तियों/लोगों का नाम गोपनीय रखा जाता है। जिले में एड्स फैलने के कारणों को गंभीरता से समझाते हुए जानकारी दी गई कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रजनन - तंत्रीय संक्रमण है तो ए आर टी सेन्टर में जांच करा सकते हैं। एचआईवी/एड्स में एन जी ओ कार्यरत हैं, ए एन सी (गर्भवती) महिलाओं के लिए अहाना कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत हैं। जेल के लिए एन जी ओ/वाई आर जी कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक एचआईवी/एड्स व्यक्ति को ए आर टी सेन्टर में लिंक करके ए आर टी की दवा दी जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य में पांच ए आर टी सेंटर है मेडिकल कॉलेज रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर में संचालित है। विश्व एड्स दिवस पर जिले के शासकीय कृषि महाविद्यालय में संगोष्ठी, रेड रिबन कार्य, जमगहना हाई स्कूल, शासकीय पी जी कालेज बैकुण्ठपुर के एन एस एस के छात्र - स्कूल छात्रों के द्वारा मानव श्रृंखला व अन्य प्रतियोगी गतिविधियों आयोजित की गई। एड्स/एचआईवी पखवाड़ा अंतर्गत जिले में नवीन कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर, जेल परिसर में, एड्स पखवाड़ा के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने का योजना बनाया गया है। गांव -गली में शोर है, एड्स एक भयानक रोग है। अपील - एचआईवी की जांच करायें, एड्स की शंका से मुक्ति पायें।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

जशपुरनगर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं चिन्हित अनुभाग स्तर पर वन अधिकार प्रकोष्ठ में मानव संसाधन के रूप में जिला स्तरीय समन्वयक तथा उपखण्ड स्तर पर एमआईएस सहायक की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिला स्तरीय चयन समिति के परीक्षण उपरान्त जिला स्तरीय समन्वयक हेतु 63 आवेदन प्राप्त है, जिसमें से 63 अपात्र तथा एमआईएस सहायक के 85 आवेदन प्राप्त है, जिसमें से 03 पात्र, 82 अपात्र पाया गया। पात्र व अपात्र सूची में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु लिखित अभ्यावेदन 03 दिसम्बर 2025 तक निर्धारित की गई है। अभ्यार्थी पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर में कार्यालयीन समय तक अभ्यादेवन प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु जिले के वेबसाईट पर अवलोकन किया जा सकता है, अथवा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जशपुर में कार्यालयीन समय पर सम्पर्क किया जा सकता है।

लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत छात्राओं को अधिकारों और सुरक्षा की विस्तृत जानकारी

छ.ग.फ्रंटलाइन

एमसीबी। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार और जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में महिला सशक्तीकरण केंद्र (हब), महिला एवं बाल विकास विभाग एमसीबी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत लिंग आधारित हिंसा समाप्ति हेतु चल रहे 16 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय मनेंद्रगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को लिंग आधारित हिंसा, डिजिटल हिंसा, अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें बताया गया कि अधिकारों, अवसरों और शिक्षा से किसी भी प्रकार का वंचन न हो, इसके लिए जागरूक व सशक्त होना आवश्यक है, ताकि समाज को हिंसा मुक्त बनाया जा सके।

इस दौरान बाल अधिकार, सामाजिक भेदभाव के सकारात्मक- नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा की गई तथा बालिकाओं को विभिन्न वीरांगनाओं के प्रेरणादायी जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को निम्न महत्वपूर्ण योजनाओं और कानूनों की जानकारी भी दी गई-लैंगिक समानता का महत्व, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सखी वन-स्टॉप सेंटर, संवेदनशीलता एवं साइबर सुरक्षा, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर-181, 1098, 1930, सुकन्या समृद्धि योजना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पॉक्सो एक्ट के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। पस्थित छात्राओं को विभिन्न योजनाओं से संबंधित ब्रोशर भी वितरित किए गए।

कार्यक्रम में मिशन शक्ति (हब) के कर्मचारी, सखी केंद्र के सदस्य, महाविद्यालय के प्राचार्य, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।

मनरेगा की डबरी ने बदली किस्मत- बुड़ार के किसान ढोलालाल बने आत्मनिर्भर किसान का नया उदाहरण

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के बुड़ार गाँव के मेहनतकश किसान ढोलालाल वर्षों से सिंचाई के अभाव की समस्या से जूझ रहे थे। केवल बारिश पर निर्भर खेती के कारण उनकी धान फसल अक्सर पानी की कमी से प्रभावित होती थी, जिससे उपज घटती और परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत पहले निर्मित एक सफल डबरी को देखकर ढोलालाल के मन में भी उम्मीद जगी। उन्होंने अपने खेत में डबरी निर्माण के लिए आवेदन किया। ग्राम सभा की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख 40 हजार रुपए की लागत से व्यक्तिगत डबरी निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई।

डबरी निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत एजेंसी के रूप में संपादित हुआ। ग्राम रोजगार सहायक और मेट ने मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता फैलाकर 30द्द40 से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को नियोजित किया। निर्धारित समय-सीमा में निर्माण पूरा किया गया, जिससे ढोलालाल की सूखी भूमि पर स्थायी जल-स्रोत तैयार हो गया।

डबरी के निर्माण से ढोलालाल की खेती को नई दिशा मिली है। वे बताते हैं पहले फसल पकने के समय पानी की कमी से उपज कम होती थी, लेकिन अब डबरी ने यह समस्या खत्म कर दी है।अब अतिरिक्त बरसाती पानी सुरक्षित होकर पूरे वर्ष सिंचाई उपलब्ध रहती है, जिससे खेती स्थिर और सुरक्षित हुई है।

सब्जी उत्पादन से बढ़ी आय, बढ़ा आत्मविश्वास

सिंचाई सुविधा में सुधार के बाद ढोलालाल अब धान के साथ रबी की फसलें भी उगा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक एकड़ भूमि में व्यावसायिक सब्जी उत्पादन शुरू किया है, जिससे उनकी वार्षिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह परिवर्तन उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रहा है।

गणना पत्रक सत्यापन की अवधि 11 तक

जशपुरनगर। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में चलाये जा रहे निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जशपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 16 दिसम्बर 2025 एवं 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जारी संशोधित कार्यक्रम अनुसार 11 दिसम्बर 2025 को गणना पत्रक सत्यापन, 16 दिसम्बर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावा आपत्ति, 16 दिसम्बर 2025 से 07 फरवरी 2026 तक सुनवाई और सत्यापन कार्य एवं 14 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन निर्धारित है।

महोरा में अश्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजित

छ.ग.फ्रंटलाइन

बैकुंठपुर। जिले के बैकुण्ठपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत महोरा के प्राथमिक शाला महोरा परिसर में 28 नवंबर 2025 को आदिम जाति कल्याण विभाग ने छुआछूत और अश्पृश्यता निवारण उद्देश्य से सद्भावना शिविर का आयोजन किया गया। भारत के महान समाज सुधारक महात्मा गांधी एवं डॉ भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुभारंभ गया। इस कार्यक्रम में समाज के सभी जाति, वर्ग के लोग उपस्थित रहे व सभी ने एकजुट होकर छुआछूत की भावना को त्यागने के लिए एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण किए, साथ ही ग्रामीणों में सद्भावना बढ़ाने कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया। शिविर में आदिम जाति कल्याण विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती उषा लकड़ा ने संविधान के अनुच्छेद 17 तथा विभिन्न अश्पृश्यता निषेध नियमों का उल्लेख करते हुए, इस कार्यक्रम के महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती वंदना राजवाडे ने छुआछूत से बचने की सलाह दी साथ ही लोगों में समानता का भाव बनाए रखने के लिए आव्हान की। बैकुण्ठपुर जनपद अध्यक्ष श्री उदय सिंह ने कहा कि सभी मनुष्यों का रक्त समान है, इसलिए जाति भेद की भावना रखना उचित नहीं हम सब इंसान है और इंसानियत हमारा धर्म है। इस कार्यक्रम में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैकुण्ठपुर श्री सिद्धार्थ खैरवार सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहें।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर (छ.ग.) पिन नं. 497001 से मुद्रित व महलपारा बैकुण्ठपुर से प्रकाशित। संपादक- कमलेश शर्मा